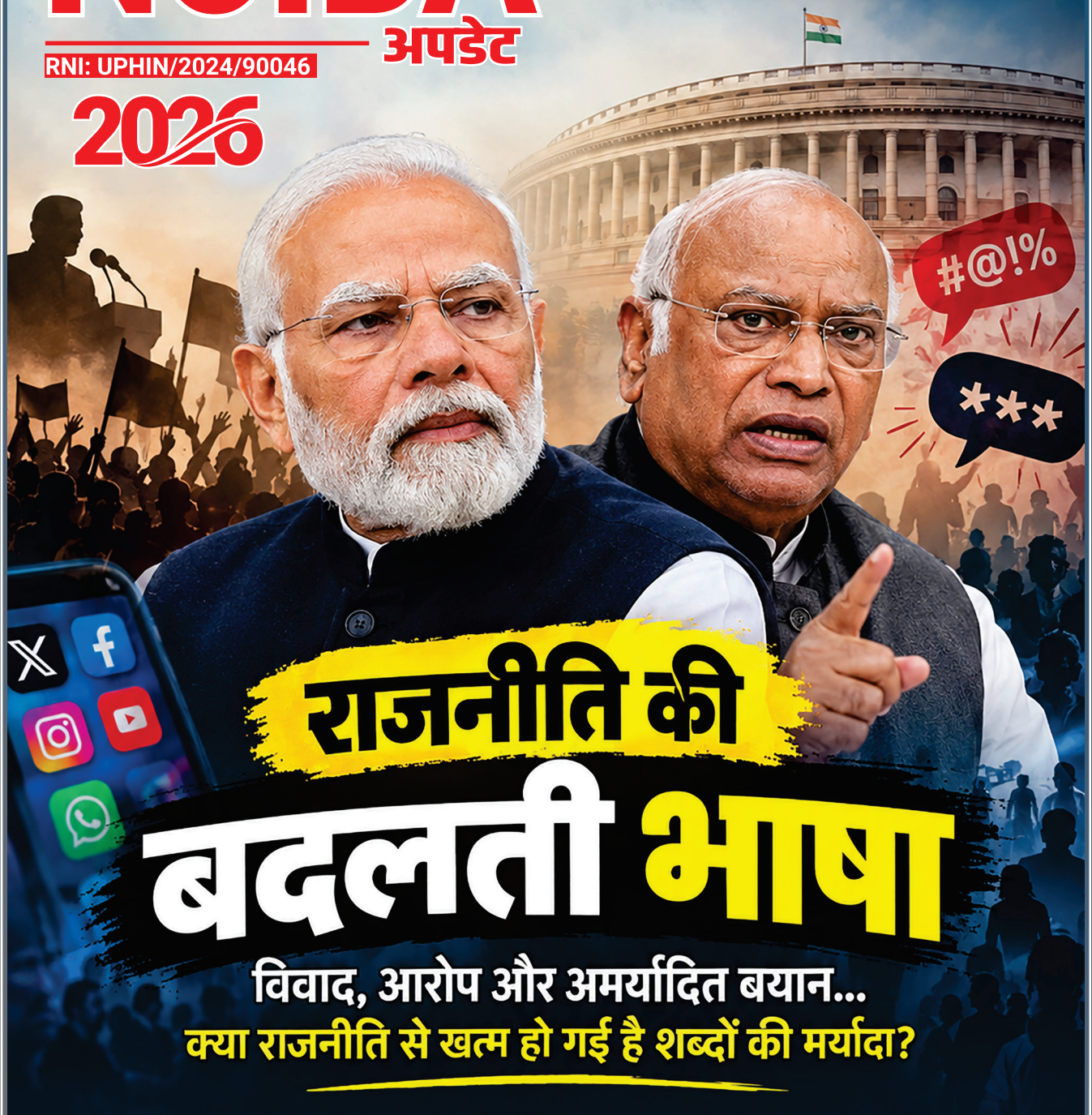
NOW NOIDA अपडेट

Volume - 03 | Issue - 11
November 2026 | Price : ₹ 10/-

RNI: UPHIN/2024/90046

2026

लोकतंत्र में
संवाद जरूरी,
अपमान नहीं



राजनीति की बदलती भाषा

विवाद, आरोप और अमर्यादित बयान...
क्या राजनीति से खत्म हो गई है शब्दों की मर्यादा?

क्यों बढ़ रहा है
अमर्यादित भाषा का चलन?

सोशल मीडिया,
ध्रुवीकरण और वायरल होने की होड़

क्या गाली-गलौज
से सत्ता का रास्ता बनता है?

MB

DIRECT FROM FACTORY

NATURE PLUS

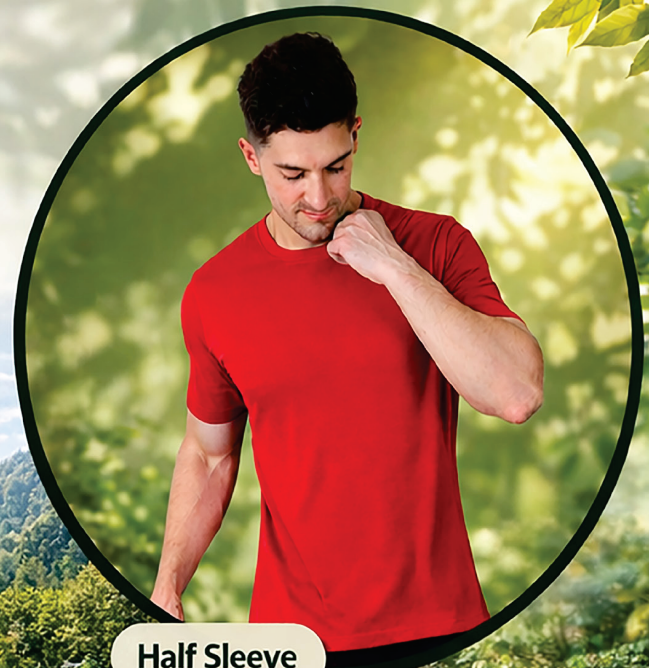
Premium Men's T-Shirts Collection

Sustainable Fabric | Soft & Comfortable

Breathable | Odour Resistant

Shop Now

WWW.MADEBYINDIA.COM



Half Sleeve

Half Sleeve T-Shirts

Stay Cool & Stylish



Full Sleeve T-Shirts

Comfort in Every Season



Polo T-Shirts

Smart Casual Look



NOW NOIDA अपडेट
सत्य से साक्षात्कार

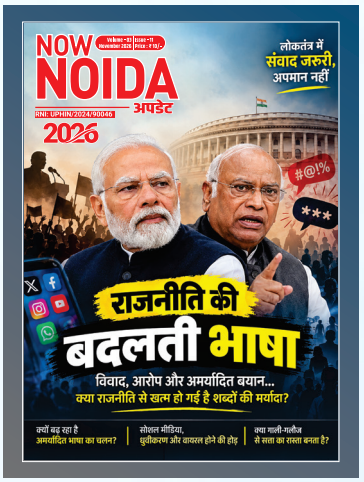
Content

Volume – 3 | Issue – 11 | November 2026 | Price : ₹10

दिल्ली-NCR में प्रदूषण
04 दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने की कैसी तैयारी, सर्दियों में बदलेंगे नियम

लॉरेंस का यूपी कनेक्शन
05 लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यूपी कनेक्शन, जांच में सामने आए नए पहलू

योगी कैबिनेट के फैसले
06 योगी कैबिनेट के 22 फैसले, निवेश और विकास को लेकर बड़े प्रस्ताव



राजनीति की भाषा
08 राजनीति की बदलती भाषा: विवाद, आरोप और अमर्यादित बयान

यूपी चुनाव 2027
10 मुस्लिम मतदाता, ओवैसी और बदलते सियासी समीकरण

टाइगर श्रॉफ - फायरिंग
11 टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, जांच का दायरा बढ़ा

गौर चौक का अंडरपास
12 गौर चौक अंडरपास से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाम से राहत

अखिलेश यादव - 2027
13 अखिलेश यादव की 2027 की सियासी रणनीति और पीडीए

NCR की जहरीली हवा
14 दिल्ली-NCR की जहरीली हवा में कौन-सा मास्क कितना असरदार?

एक देश, एक चुनाव
17 एक देश, एक चुनाव: फायदे, चुनौतियां और आगे की राह

कैंसर दवाओं पर ड्रेड
22 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन सीमा, मरीजों को राहत की उम्मीद

मतदाता सूची पर संग्राम
18 चुनाव आयोग और विरोध

सीवान में पटाखा विस्फोट
25 लापरवाही और सुरक्षा पर सवाल

इकोटेक-12 का दशहरा
20 इकोटेक-12 का दशहरा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का बड़ा आयोजन

रिश्तों में लालच और हत्या
28 मेरठ समेत चर्चित मामलों की पड़ताल

EDITORIAL TEAM

Editor
Sandeep Kumar Ojha

Noida Bureau
Sazid Ali & Nirmal Gaur

Senior Correspondent
Abhishek Pandey & Rishabh Chhabra

Layout Design
Babli Ansari

Legal Advisor
Md. Shahid, Lawyer

Managing Director
Sandeep Ojha

Director & Publication
MBI DIGITAL PVT. LTD.

Registered Office
Plot No. 99, Ecotech-03, Udhyog Kendra-2, Greater Noida – 201306

Printer & Publisher
MBI DIGITAL PVT. LTD. Plot No. 99, Ecotech-03, Udhyog Kendra-2, Greater Noida – 201306
Mobile No. 7428827715, 9220407108
Email : infonownoida@gmail.com

Published by Sandeep Kumar Ojha, Printer and Publisher for MBI Digital Pvt. Ltd., from Plot No. 99, Ecotech-3, Udyog Kendra-2, Greater Noida (Gautambudh Nagar), and printed at Chandra Prabhu Offset Printing Works Pvt. Ltd. Plot No. 69, Ecotech-12, Greater Noida, Uttar Pradesh – 201318.
Editor: Sandeep Kumar Ojha
(RNI: UPHIN/2024/90046).



सम्पादकीय...

संदीप ओझा
संपादक

www.nownoida.com



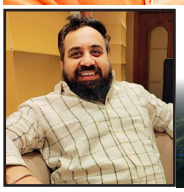
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए इस बार पहले से कई कदम उठाए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली का AQI 244 तक पहुंच गया था, जिसके बाद पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया। अब दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक के लिए सर्दियों की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश होगी। इस बार तैयारी का खास हिस्सा प्रदूषण बढ़ने के बाद कदम उठाने के बजाय पहले से नियम लागू करना है। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग विभाग कितनी तेजी से काम करते हैं और नियमों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।

प्रदूषण बढ़ने के पीछे केवल एक कारण नहीं है। दिल्ली और आसपास के शहरों में वाहनों का धुआं, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, कारखानों से निकलने वाला धुआं और खुले में कचरा जलाना हवा को प्रभावित करते हैं। सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में प्रदूषक कणों के फैलाव में कमी आने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं से उठने वाला धुआं भी कुछ दिनों में प्रदूषण बढ़ा सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकता। इस बार अधिकारियों ने दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दूसरे एनसीआर क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया है। दिल्ली में आने वाले उन ट्रकों को दूसरे रास्तों से भेजने की योजना है, जिन्हें राजधानी में प्रवेश की जरूरत नहीं है। सड़कों पर मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय भी तेज किए जाएंगे। इन सभी कदमों का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले अलग-अलग स्रोतों पर एक साथ काम करना है।

इस बार दिल्ली की शीतकालीन कार्ययोजना में वाहनों और निर्माण कार्यों को लेकर कुछ अहम नियम भी शामिल हैं। एक नवंबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत, बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर भी निर्धारित छूट और नियमों के अनुसार रोक लगाई जाएगी। एक नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना घोषित की गई है। आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं पर लागू छूट अलग हो सकती है। इसके अलावा, अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क बढ़ाने, कार्यालयों के समय में बदलाव और एक नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराने की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी केंद्रों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 करने और 334 जांच दल तैनात करने की भी घोषणा की गई है। इन कदमों का उद्देश्य यातायात का दबाव घटाना, धूल पर नियंत्रण रखना और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना है।

हालांकि, प्रदूषण पर नियंत्रण का असली आकलन केवल घोषित योजनाओं से नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में होने वाले सुधार से होगा। ग्रैप के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने पर चरणबद्ध तरीके से सख्ती बढ़ाई जाती है। पहले चरण में सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने और खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई जैसे उपाय किए जाते हैं। स्थिति बहुत खराब होने पर वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लग सकती हैं। ऐसे में लोगों को रोजाना वायु गुणवत्ता की जानकारी लेते रहना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रदूषण बढ़ने के दिनों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और जरूरत के अनुसार बाहरी गतिविधियां सीमित करनी चाहिए। आम लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कम करके सार्वजनिक परिवहन अपना सकते हैं और कचरा या पत्तियां खुले में जलाने से बच सकते हैं। साथ ही, प्रशासन को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर लगातार नजर रखनी होगी और दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों के बीच तालमेल बनाए रखना होगा। इस बार योजनाओं और निगरानी की व्यवस्था पहले से तैयार है, लेकिन सर्दियों में हवा कितनी साफ रह पाएगी, यह मौसम, क्षेत्रीय प्रदूषण और जमीनी स्तर पर इन उपायों के पालन पर निर्भर करेगा।





ऋषभ कांत छाबड़ा
विशेष संवाददाता

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम देश में कई चर्चित आपराधिक घटनाओं के साथ जुड़ता रहा है। इस गिरोह की गतिविधियों में उत्तर प्रदेश का कनेक्शन भी लगातार सामने आता रहा है। जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यूपी के कुछ आरोपियों के नाम शूटरों की भूमिका, हथियारों की व्यवस्था और अपराध के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले में भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में दो महिलाओं के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के अनुसार, वे कथित तौर पर घटना से जुड़े लोगों की मदद कर रही थीं और घटना के बाद भागने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम जांच में सामने आना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, आपसी संपर्क और गिरोह से संभावित संबंधों की पड़ताल करती हैं। यूपी का नाम बार-बार सामने आने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य के कुछ इलाकों का इस्तेमाल अपराधियों की आवाजाही, संपर्क और छिपने के लिए किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब अलग-अलग मामलों की जांच और सामने आए सबूतों से ही स्पष्ट हो सकता है।

उत्तर प्रदेश का कनेक्शन सामने आने वाले चर्चित मामलों में वर्ष 2024 में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या भी शामिल है। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, तीन हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई थीं। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला था। धर्मराज कश्यप का नाम भी इस मामले में सामने आया। जांच के दौरान कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश से हुई। इस मामले ने दिखाया कि बड़े शहरों में हुई आपराधिक घटनाओं की जांच के तार दूसरे राज्यों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, किसी आरोपी का यूपी का निवासी होना और पूरे गिरोह का राज्य में मजबूत आधार होना दो अलग बातें हैं। इसके लिए गिरोह के संपर्कों, आर्थिक लेनदेन और अपराध की योजना से जुड़े प्रमाणों की जरूरत होती है। जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में आरोपियों के आपसी संबंधों और उनकी कथित भूमिका को जोड़कर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करती हैं।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े बताए गए दूसरे मामलों में भी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों का जिक्र हुआ है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर गोलीबारी के मामले में आगरा के बाह क्षेत्र के बिजौली गांव के विष्णु कुशवाहा को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, उस पर गोलीबारी की जिम्मेदारी सौंपे जाने का आरोप था। इसके बाद आगरा के एक अन्य आरोपी प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई। इसी तरह, गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में हुई हत्या की जांच में भी उत्तर प्रदेश में आरोपियों की मौजूदगी और हथियारों से जुड़े कुछ पहलुओं का उल्लेख किया गया था। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान असद और अनस नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर आई। वहीं, 29 मई 2025 को उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल और दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद के लोनी निवासी नवीन कुमार घायल हुआ था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे तथा उसके गिरोह से जुड़े होने की बात सामने आई थी। इन घटनाओं से पता चलता है कि अलग-अलग मामलों में यूपी के कुछ लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है, लेकिन हर मामले के तथ्य और आरोप अलग-अलग हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे मामलों में बार-बार क्यों सामने आता है और गिरोहों के कथित नेटवर्क को रोकने के लिए क्या जरूरी है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बड़े शहरों और कई राज्यों से जुड़ी सड़क तथा रेल व्यवस्था के कारण यहां से लोगों की आवाजाही व्यापक है। लेकिन केवल इन कारणों से किसी क्षेत्र को अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए ठोस सबूत और जांच के निष्कर्ष जरूरी हैं। संगठित अपराध से निपटने में पुलिस के बीच बेहतर तालमेल, आरोपियों के संपर्कों की जांच, अवैध हथियारों की आपूर्ति पर रोक और अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले सहित अन्य घटनाओं में भी जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि किसने क्या भूमिका निभाई और अलग-अलग आरोपियों के बीच संबंध किस तरह बने। साथ ही, सोशल मीडिया पर गिरोहों के नाम का इस्तेमाल कर डर फैलाने या जिम्मेदारी लेने के दावों की भी जांच जरूरी है। फिलहाल उपलब्ध घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े मामलों की जांच कई राज्यों तक फैली है और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग भी इनमें आरोपी या संदिग्ध के रूप में सामने आए हैं। इस पूरे नेटवर्क की वास्तविक तस्वीर जांच और अदालत में सामने आने वाले सबूतों से ही स्पष्ट होगी।







संदीप ओझा
संपादक

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने, चार लिंक एक्सप्रेसवे बनाने और प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने नावों और जल परिवहन को व्यवस्थित करने, कंपनियों के विलय से जुड़े नियमों में स्पष्टता लाने तथा भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इन फैसलों के बीच लखनऊ-हरदोई सीमा पर विकसित हो रहा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क भी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास रणनीति का अहम हिस्सा है।

पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी, एक गाय पर ₹50 हजार अनुदान

कैबिनेट के फैसलों में पशुपालन को किसानों की आय का मजबूत माध्यम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्ताव के तहत एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने और पशु बीमा की लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार तथा 15 प्रतिशत हिस्सा पशुपालक द्वारा वहन करने की व्यवस्था शामिल है। सरकार का उद्देश्य उन्नत नस्लों को बढ़ावा देना, पशुओं की उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

योजना के तहत गाय की नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने की दिशा में सहायता देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में पशुपालन से जुड़ी योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, अनुदान पाने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की शर्तें संबंधित दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होंगी।

शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने राहत से जुड़ा फैसला लिया है। अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत सरकार प्रत्येक कर्मचारी के बीमा प्रीमियम के लिए 3,000 रुपये देगी और इस पर कुल 14.41 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा देने का प्रावधान बताया गया है। बेसिक शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के 1,22,305 कर्मचारियों को भी चिकित्सा सुविधा के दायरे में लाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।



चार लिंक एक्सप्रेसवे पर ₹17,542 करोड़ खर्च, तीन साल में निर्माण का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने और प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर सहमति दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 17,542 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मॉडल पर कराने की योजना है। परियोजनाओं को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि निर्माण करने वाली कंपनियों को पांच साल तक एक्सप्रेसवे के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज और लगभग 74 किलोमीटर लंबा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे भी योजना का हिस्सा हैं। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों पैकेजों की कुल लंबाई करीब 106 किलोमीटर बताई गई है।

इन परियोजनाओं का महत्व केवल यात्रा का समय कम करने तक सीमित नहीं है। बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक माल पहुंचाना आसान हो सकता है, परिवहन लागत घट सकती है और आसपास के इलाकों में नए कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं। खासकर जेवर क्षेत्र में औद्योगिक और हवाई अड्डे से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार के लिहाज से बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, परियोजनाओं का वास्तविक लाभ निर्माण की गति, भूमि और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के समय पर पूरा होने तथा उनके संचालन पर निर्भर करेगा।

कैबिनेट ने निवेश और उद्योगों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। ग्रेटर नोएडा में एकागो हॉस्पिटेलिटी के 654 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति के तहत चार कंपनियों के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने पर भी सहमति दी गई। इनमें नोएडा में हैवेल्स का 889 करोड़ रुपये, अमेरियोराइड इंडिया एलएलपी का 112 करोड़ रुपये, मेटलाइफ ग्लोबल का 84 करोड़ रुपये और एलजी सॉफ्ट का 634 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है। ये निवेश प्रस्ताव प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश का हिस्सा हैं, हालांकि प्रस्तावित निवेश और जमीन पर शुरू होने वाली परियोजनाएं अलग-अलग चरण हैं।

लखनऊ का PM MITRA टेक्सटाइल पार्क: 1,000 एकड़ में कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने की योजना

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात हो और लखनऊ-हरदोई सीमा पर विकसित हो रहे PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। लगभग 1,000 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस पार्क का उद्देश्य कपड़ा और परिधान उद्योग की पूरी उत्पादन श्रृंखला को एक ही औद्योगिक परिसर में उपलब्ध कराना है। इसमें कताई, बुनाई, कपड़े की प्रोसेसिंग, रंगाई-छपाई और तैयार परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इससे कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक की प्रक्रिया अधिक संगठित हो सकती है और उद्योगों की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

इस परियोजना को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए मई 2026 में 546.51 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत आउटर रिंग रोड के रैथा अंडरपास से टेक्सटाइल पार्क के प्रवेश द्वार तक लगभग 14.28 किलोमीटर लंबी छह लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। साथ ही आईआईएम लखनऊ से रैथा अंडरपास तक लगभग 8.7 किलोमीटर सड़क को दो लेन में चौड़ा और सुदृढ़ करने का काम भी इसमें शामिल है। इस कनेक्टिविटी परियोजना का मकसद औद्योगिक परिसर तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही आसान बनाना और भविष्य में स्थापित होने वाली इकाइयों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है।

टेक्सटाइल पार्क के लिए केवल सड़क ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी, आंतरिक सड़कें, अपशिष्ट जल प्रबंधन और उद्योगों के लिए तैयार सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर विकसित करने की योजना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी वाली विशेष प्रयोजन कंपनी बनाई गई है। परियोजना से लगभग एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। यह अनुमानित लक्ष्य है; वास्तविक रोजगार पार्क के विकास, वहां स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों और उनके संचालन पर निर्भर करेगा।

टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने मई 2026 में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के तहत चार बंद कताई मिलों की लगभग 251.8 एकड़ जमीन हस्तकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इन जमीनों का इस्तेमाल नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए किया जाना है। यह कदम लखनऊ के PM MITRA पार्क से अलग है, लेकिन प्रदेश में कपड़ा उद्योग के लिए औद्योगिक आधार तैयार करने की व्यापक रणनीति से जुड़ा है।

लखनऊ की चिकनकारी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कपड़ा कारोबार को आधुनिक उत्पादन, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बड़े बाजारों से जोड़ने की संभावनाएं भी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती हैं। यदि योजनानुसार निवेश और औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं, तो इससे बड़े निवेशकों के साथ छोटे उद्यमियों, कारीगरों और स्थानीय श्रमिकों को भी अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए परियोजना का समय पर विकास, निवेशकों की भागीदारी और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता अहम होगी।



नाविकों का बीमा, कंपनियों के मर्जर पर नियम और भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए मोटर चालित और बिना मोटर वाली नावों के पंजीकरण की व्यवस्था विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी बनाने और यात्रियों तथा नाविकों के बीमा का प्रावधान करने की योजना है। गंगा और यमुना समेत प्रदेश की 11 नदियों पर जल परिवहन की संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे नावों का रिकॉर्ड तैयार करने, संचालन पर निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

कंपनियों के विलय और विभाजन से जुड़े स्टांप ड्यूटी प्रावधानों में भी स्पष्टता लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और संपत्ति शामिल होने की स्थिति में उस पर दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का प्रावधान है। इसका उद्देश्य कंपनियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में स्पष्ट नियम उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके अलावा झांसी और ललितपुर में 6.5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है। इन फैसलों का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ाना है।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के फैसलों में किसानों और पशुपालकों की आय, कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा, सड़क संपर्क, औद्योगिक निवेश और जल परिवहन जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वहीं, लखनऊ का PM MITRA टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश की दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मंजूर प्रस्ताव कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं, निवेश कितना वास्तविक रूप लेता है और रोजगार व सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक किस हद तक पहुंचता है।



क्या अपशब्दों से तय होगी सत्ता की राह, कहां खो गई मर्यादा?





संदीप ओझा
संपादक

भारतीय राजनीति में कभी नीतियों, विचारधाराओं और विकास के मुद्दों पर होने वाली बहस अब कई बार व्यक्तिगत आरोपों, अपमानजनक टिप्पणियों और अमर्यादित भाषा तक पहुंच जाती है। चुनावी मंच हो या राजनीतिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया हो या संसद के बाहर की बयानबाजी, नेताओं और उनके समर्थकों की भाषा लगातार चर्चा का विषय बन रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध जताने के लिए अब शब्दों की मर्यादा जरूरी नहीं रह गई है? क्या तीखी और अपमानजनक भाषा के जरिए राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है? चिंता की बात यह भी है कि इस प्रवृत्ति में केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि आंदोलनों में शामिल कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जंतर-मंतर पर की गई अभद्र टिप्पणियों से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान तक, राजनीतिक संवाद के स्तर पर बहस तेज हुई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में अमर्यादित भाषा का चलन क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है।

राजनीति में शब्दों की मर्यादा पर क्यों उठ रहे सवाल?

राजनीति में विरोध और आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, विपक्ष के दावों को चुनौती देना और नेताओं के फैसलों की आलोचना करना राजनीतिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जब वैचारिक असहमति व्यक्तिगत अपमान और परिवार के सदस्यों पर की गई टिप्पणियों में बदल जाती है, तो बहस का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है।

हाल के दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणियों का मामला चर्चा में आया। प्रदर्शन के आयोजकों और उसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित युवाओं को ऐसी हरकतों से बचने की सलाह दी और उन्हें माफ करने की बात कही। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जरूरी है?

यह समस्या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित मानकर नहीं देखी जा सकती। अलग-अलग दलों के नेताओं के विवादित बयान समय-समय पर राजनीतिक बहस को प्रभावित करते रहे हैं। हालांकि, हर बयान की प्रकृति, संदर्भ और गंभीरता अलग होती है। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर सभी नेताओं या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।

लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि नेता केवल अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखते, बल्कि उनके शब्दों का असर लाखों समर्थकों और आम नागरिकों पर पड़ सकता है। जब बड़े नेता मर्यादा की सीमा पार करते हैं, तो उनके समर्थकों के बीच भी उसी तरह की भाषा को सामान्य मानने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।



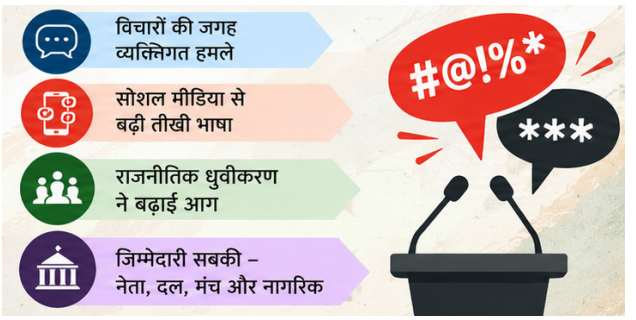
खड़गे के बयान से पटना में विवाद, कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

बिहार की राजधानी पटना में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। बापू सभागार में भाषण के बीच एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात रखी। उसने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया।

हंगामे के दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पिटाई किए जाने की बात सामने आई। बाद में उसे सभागार से बाहर निकाल दिया गया। उसकी पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई, जो छपरा से कार्यक्रम में शामिल होने आया था। बाहर आने के बाद उसने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने उसे गलतफहमी में बीजेपी समर्थक समझ लिया। उसने अपने बयान के संदर्भ में कहा कि वह देश में विद्रोह होने की बात कर रहा था, जिसके बाद ही नरेंद्र मोदी के जाने की बात कही जा सकती है।

इस घटनाक्रम ने दो अलग-अलग सवाल खड़े किए। पहला, राजनीतिक मंच पर विरोध या असहमति जताने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? दूसरा, क्या किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान को लेकर अनुमान लगाकर उसके साथ हिंसक व्यवहार करना उचित है? किसी बयान से असहमति होने पर उसका जवाब तर्क और लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मारपीट को सही नहीं ठहराया जा सकता।

खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की। वहीं,



कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके बयान का बचाव किया। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझने की जरूरत है और उन्होंने लोकतंत्र तथा कथित वोट चोरी के मुद्दे को इससे जोड़ा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी खड़गे के बयान का समर्थन किया, जबकि प्रमोद तिवारी ने कहा कि बयान को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया।

दूसरी ओर, बीजेपी ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक भाषा और प्रधानमंत्री के प्रति उसके रवैये से जोड़कर हमला बोला। इस विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने खड़गे से इस बारे में बात नहीं की है और वह उनके बयान पर सफाई नहीं दे सकते। उनके बयान से यह स्पष्ट हुआ कि विपक्षी खेमे के भीतर भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी।

यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक बयान केवल कहे गए शब्दों तक सीमित नहीं रहते। उनके बाद पार्टी के नेता बचाव में उतरते हैं, विरोधी दल राजनीतिक हमला करते हैं और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो जाती है। कई बार मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और राजनीति बयान की व्याख्या तथा उसके बचाव तक सिमट जाती है।

सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और वायरल होने की होड़

राजनीति में अमर्यादित भाषा के बढ़ते चलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें राजनीतिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति और समर्थकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने की होड़ महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इन कारणों का प्रभाव हर घटना में एक जैसा नहीं होता और किसी एक वजह को पूरी समस्या का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सोशल मीडिया ने नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सीधे जनता तक पहुंचने का अवसर दिया है। लेकिन इसी व्यवस्था में तीखे बयान, विवादित वीडियो और अपमानजनक टिप्पणियां तेजी से फैल सकती हैं। किसी बयान के वायरल होने से नेता या कार्यकर्ता को तत्काल चर्चा मिलती है। इसके कारण कुछ लोगों में ऐसी भाषा इस्तेमाल करने का प्रलोभन पैदा हो सकता है, जो सामान्य राजनीतिक बहस की तुलना में अधिक आक्रामक हो।

AI से तैयार किए गए वीडियो और दूसरी डिजिटल सामग्री ने भी राजनीतिक संवाद की चुनौतियां बढ़ाई हैं। पटना के विवाद के बीच कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसी सामग्री का राजनीतिक संदर्भ में इस्तेमाल करते समय यह समझना जरूरी है कि डिजिटल प्रस्तुति वास्तविक घटनाओं का सटीक चित्रण हो, यह जरूरी नहीं है। दर्शकों को वीडियो की प्रकृति और संदर्भ समझने की जरूरत है।

राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इस प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। जब समर्थक किसी नेता या दल को अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं, तो विरोधी पक्ष की आलोचना को कई बार व्यक्तिगत हमले के रूप में लिया जाता है। इसके जवाब में भाषा अधिक आक्रामक हो सकती है। ऐसे माहौल में तर्क, तथ्य और नीतियों पर चर्चा की जगह आरोप-प्रत्यारोप को अधिक महत्व मिलने लगता है।

हालांकि, यह मानना भी सही नहीं होगा कि राजनीति में तीखी भाषा का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया के आने के बाद शुरू हुआ। राजनीतिक विरोध में व्यक्तिगत टिप्पणियां पहले भी होती रही हैं। फर्क यह है कि अब डिजिटल मंचों के कारण ऐसी टिप्पणियां कम समय में बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकती हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है।

क्या गाली-गलौज से सत्ता का रास्ता बनता है?

राजनीति में आक्रामक भाषा कभी-कभी समर्थकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे किसी नेता को तत्काल चर्चा मिल सकती है और समर्थकों के बीच उसकी छवि मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गाली-गलौज ही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। चुनावों में मतदाताओं के फैसले पर विकास, रोजगार, महंगाई, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व, संगठन और स्थानीय मुद्दों जैसे अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है।

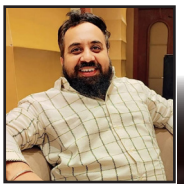
समस्या तब गंभीर होती है, जब राजनीतिक दल अपने नेताओं या कार्यकर्ताओं की अमर्यादित टिप्पणियों को रोकने के बजाय उनका बचाव करने लगते हैं। यदि किसी विवादित बयान के बाद पार्टी के नेता उसे सही ठहराने में जुट जाएं, तो सार्वजनिक संवाद में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। इसके उलट, यदि दल अपने नेताओं से संयमित भाषा की अपेक्षा करें और गलत व्यवहार पर स्पष्ट रुख अपनाएं, तो राजनीतिक संवाद का स्तर बेहतर हो सकता है।

इस मामले में राजनीतिक दलों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों, आयोजकों और आम नागरिकों की भी भूमिका है। प्रदर्शन के आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध के नाम पर हिंसा या व्यक्तिगत अपमान को बढ़ावा न मिले। नेताओं को अपने समर्थकों के व्यवहार पर जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए। वहीं, नागरिकों को किसी बयान या वीडियो को बिना संदर्भ समझे साझा करने से बचना चाहिए।

भारतीय राजनीति के सामने असली चुनौती यह नहीं है कि कौन सबसे तीखा बयान देता है, बल्कि यह है कि कौन असहमति के बावजूद लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखता है। प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो या किसी दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ अपमानजनक बयान, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का अधिकार और सार्वजनिक भाषा की जिम्मेदारी साथ-साथ चलनी चाहिए। सत्ता की राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध और अपमान के बीच की सीमा मिटने लगे तो नुकसान केवल किसी एक नेता या दल का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श का होता है।







ऋषभ कांत छाबड़ा
विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। इस बार चर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले की नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश करती दिख रही है। हैदराबाद से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत इलाकों में से एक आजमगढ़ को अपने निशाने पर लिया है। यह वही क्षेत्र है, जहां मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का लंबे समय तक राजनीतिक प्रभाव रहा है। ओवैसी ने आजमगढ़ की सभा में मुस्लिम समाज से यादव परिवार की लाल टोपी के पीछे चलने के बजाय अपना राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करने की अपील की। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन तो लिया, लेकिन उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इन बयानों के जरिए ओवैसी मुस्लिम समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनौती इसलिए अहम है, क्योंकि प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से उसके समर्थन में रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2027 के चुनाव में ओवैसी इस परंपरागत राजनीतिक आधार में सेंध लगा पाएंगे या उनकी सक्रियता केवल चुनावी चर्चा तक सीमित रह जाएगी?

ओवैसी की रणनीति को समझने के लिए आजमगढ़ के साथ रामपुर की राजनीति पर नजर डालना भी जरूरी है। रामपुर लंबे समय तक आजम खान और समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां कई ऐसे घटनाक्रम हुए, जिन्होंने पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त होने के बाद स्वार-टांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें अपना दल के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज की। अब इस क्षेत्र में ओवैसी की सक्रियता को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्वार-टांडा में करीब 3.10 लाख मतदाता हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यहां मुस्लिम आबादी लगभग 70 प्रतिशत है। इस वजह से यह सीट राजनीतिक दलों के लिए खास महत्व रखती है। ओवैसी की जनसभा के बाद यह चर्चा तेज हुई है कि क्या वह मुस्लिम मतदाताओं के सामने एक वैकल्पिक नेतृत्व पेश कर पाएंगे। हालांकि, किसी सभा में भीड़ जुटना और चुनाव में वोट हासिल करना अलग-अलग बातें हैं। ओवैसी की वास्तविक ताकत का पता संगठन की मजबूती, स्थानीय उम्मीदवारों और चुनावी अभियान के दौरान ही चलेगा। फिर भी रामपुर जैसे क्षेत्र में उनकी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती बढ़ा सकती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश में उनकी आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत मानी जाती है, जबकि कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। वर्ष 2012 के बाद समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिलता रहा है। इसकी वजह पार्टी की राजनीतिक पहचान, स्थानीय नेताओं का प्रभाव और भाजपा के मुकाबले मजबूत विकल्प की धारणा रही है। लेकिन अब ओवैसी इसी समर्थन आधार के भीतर मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि मुस्लिम समाज को केवल किसी दल की जीत सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने नेताओं और प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह संदेश उन मतदाताओं के एक हिस्से को आकर्षित कर सकता है, जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपने परंपरागत समर्थकों का भरोसा बनाए रखे और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दे। यदि ओवैसी कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं और मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा उनकी ओर जाता है, तो मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। इसका लाभ भाजपा या उसके सहयोगी दलों को भी मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी मतों का बंटवारा चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। हालांकि, यह परिणाम पहले से तय नहीं है और मतदाताओं का फैसला कई स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करेगा।



2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती जरूर पेश करती है, लेकिन इसे अखिलेश यादव के लिए तत्काल खतरे के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। चुनाव में केवल बयान और सभाएं ही निर्णायक नहीं होतीं; संगठन, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और मतदाताओं का भरोसा भी अहम भूमिका निभाते हैं। ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करना और अलग-अलग जिलों में भरोसेमंद स्थानीय नेतृत्व खड़ा करना है। वहीं, समाजवादी पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह मुस्लिम मतदाताओं सहित अपने व्यापक सामाजिक आधार को साथ लेकर चल सकती है। यदि ओवैसी आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो मुस्लिम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का सवाल चुनावी बहस के केंद्र में आ सकता है। इसके उलट, यदि वह अपने समर्थन को वोटों में बदलने में सफल नहीं होते, तो उनकी कोशिशों का असर सीमित रह सकता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 की तैयारी में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की चुनौती समाजवादी पार्टी के चुनावी आधार को कितना प्रभावित करती है और अखिलेश यादव इस नई राजनीतिक चुनौती का सामना किस रणनीति से करते हैं।





बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 18 अक्टूबर 2026 को हुई इस घटना में पुलिस ने तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया, जबकि हथियारों की कथित सप्लाई से जुड़े चार अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। अब मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हमले की साजिश, हथियारों के नेटवर्क और आरोपियों के आपसी संपर्कों की जांच जारी हैं।

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचे अभिनेता

घटना रविवार, 18 अक्टूबर की शाम की है। टाइगर श्रॉफ जुहू स्थित पुष्पा नारसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकल रहे थे। इसी दौरान दो लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं, जबकि तीसरा कथित आरोपी मोटरसाइकिल पर मौजूद था। पुलिस को शक है कि हमलावरों ने वारदात से पहले कई दिनों तक अभिनेता की गतिविधियों और इलाके की रेकी की थी।

पुलिस के मुताबिक, कार पर पांच से छह राउंड फायरिंग की गई। टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, हालांकि चोटें आई है, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस इब्राहिम बलोच को गोली लगी। घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में 11 अक्टूबर को भी संदिग्धों के ग्राउंड के आसपास पहुंचने की जानकारी सामने आई है, हालांकि उस दिन हमले की कोशिश हुई थी या नहीं, इसकी पुष्टि होना बाकी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के नाम से जिम्मेदारी लेने वाला संदेश और ऑडियो सामने आया। इसमें टाइगर को निशाना बनाने के पीछे सलमान खान के साथ उनके पेशेवर संबंधों का जिक्र किए जाने की बात कही गई। हालांकि, इस दावे और ऑडियो की प्रामाणिकता को जांच के बिना अंतिम सच नहीं माना जा सकता।

कोटा से तीन संदिग्ध गिरफ्तार, रेकी और फरार होने की जांच

पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली, जब तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। रिपोर्टों के मुताबिक, वे पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे थे। उनकी पहचान रेहान उर्फ सुक्का, ऋतिक उर्फ रोशन और फूल सिंह के रूप में बताई गई है। जांच में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी अहम सुराग बनी। पुलिस के मुताबिक, फायरिंग के बाद कथित हमलावर बाइक से फरार हुए और बाद में उसे अंधेरी इलाके में छोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज और बाइक से जुड़े सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ी। कोटा से गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को कानूनी प्रक्रिया के तहत मुंबई लाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उनसे पूछताछ की गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की योजना किसने बनाई, आरोपियों को हथियार किसने उपलब्ध कराए और वारदात के बाद उन्हें भागने में किसने मदद की। उनके मोबाइल फोन, संपर्कों और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी मामले की अहम कड़ी मानी जा रही है।

हथियार सप्लाई नेटवर्क में चार और गिरफ्तार

20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुणाल, सुमित, राधा और बबीता नाम के चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, इनकी भूमिका कथित तौर पर हथियारों की सप्लाई और वारदात से जुड़े इंतजामों में थी। रिपोर्टों में दावा किया गया कि अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस मुंबई पहुंचाए गए थे। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि हथियार किसने खरीदे, उन्हें किन लोगों के जरिए पहुंचाया गया और फायरिंग करने वालों से इन चारों का क्या संबंध था। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां कई शहरों तक फैली हो सकती हैं। हालांकि, गिरफ्तार किए गए लोगों की वास्तविक भूमिका और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

सलमान खान को निशाना बनाने का एंगल, गैंग कनेक्शन की जांच

इस मामले में सलमान खान से जुड़ा कथित एंगल भी सामने आया है। कुछ रिपोर्टों में पुलिस जांच के हवाले से दावा किया गया कि हमलावर पहले सलमान खान को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर कथित तौर पर योजना बदलने और टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही गई है। फिलहाल इसे जांच में सामने आया दावा ही माना जाना चाहिए, न कि साबित हो चुका तथ्य। पुलिस कथित गैंग कनेक्शन, सोशल मीडिया पर जारी संदेशों और आरोपियों के आपसी संपर्कों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमले का निर्देश किसने दिया और हथियारों की व्यवस्था के पीछे कौन लोग थे। किसी गैंग के नाम से जिम्मेदारी लेने वाला संदेश अपने आप में उसकी संलिप्तता का निर्णायक प्रमाण नहीं है।

सामने आई जानकारी के मुताबिक, तीन संदिग्धों और हथियारों की कथित सप्लाई से जुड़े चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बावजूद हमले की पूरी साजिश, हथियारों के स्रोत और सलमान खान से जुड़े कथित एंगल पर अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की भूमिका का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।





ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले करीब पांच लाख लोगों के लिए इस दिवाली से बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से जिस गौर चौक के जाम ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, अब उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा गौर चौक अंडरपास अब अपने अंतिम चरण में है और अधिकारियों के अनुसार 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह 92 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा 700 मीटर लंबा और 6-लेन का अंडरपास है जो दिवाली तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

गौर चौक के जाम से मिलेगी राहत, रोजाना लाखों गाड़ियां होती हैं प्रभावित

गौर चौक ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहां से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। यह चौराहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर, क्रॉसिंग रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। सुबह और शाम के समय यहां ऐसा जाम लगता है कि लोगों को आधा-आधा घंटा इसी चौराहे पर फंसना पड़ता है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल बसें और एंबुलेंस तक इस जाम में फंस जाती हैं। पिछले पांच सालों से लोग लगातार इस अंडरपास की मांग कर रहे थे और आखिरकार अब यह सपना सच होने जा रहा है।

92 करोड़ की लागत से बन रहा अंडरपास, फिनिशिंग का काम बाकी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल विजय रावल ने बताया कि अंडरपास का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। केवल फिनिशिंग टच जैसे रोड मार्किंग, दीवारों पर पेंटिंग और लाइटिंग का काम बाकी है। अंडरपास के अंदर की दीवारों पर प्रकृति और गौतम बुद्ध से जुड़ी सुंदर पेंटिंग बनाई जा रही हैं ताकि अंदर से गुजरते समय लोगों को एक अच्छा अनुभव मिले। साथ ही प्राधिकरण ने गौर चौक के पास दो यू-टर्न भी बनाए हैं और अंडरपास के समानांतर चलने वाली सड़क को भी दोबारा से बनाया गया है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके।

यह प्रोजेक्ट मूल रूप से 15 अगस्त तक पूरा होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और बरसात के कारण इसकी डेडलाइन आगे बढ़ गई। पहले जमीन अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में भी काफी समय लगा था। लेकिन अब प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि दिवाली से पहले इसे हर हाल में खोल दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार दिवाली का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ जाती है और जाम की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

गौर सिटी समेत आसपास की सोसाइटियों को होगा फायदा

इस अंडरपास के बनने से सबसे बड़ा फायदा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की उन तमाम सोसाइटियों को होगा जो गौर चौक के आसपास बनी हुई हैं। गौर सिटी, चेरी काउंटी, पंचशील ग्रीन, इकोविलेज, आम्रपाली लेजर वैली जैसी बड़ी-बड़ी सोसाइटियों के लोग रोजाना इसी चौराहे से होकर गुजरते हैं। अभी तक उन्हें नोएडा जाने के लिए गौर चौक पर लंबा जाम झेलना पड़ता था, लेकिन अंडरपास खुलने के बाद वे सीधे बिना रुके निकल सकेंगे। यह अंडरपास ताज हाईवे के समानांतर बनाया गया है और यह सीधे ग्रेटर नोएडा को गौर सिटी और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। स्थानीय निवासियों में इसको लेकर काफी उत्साह है।

छह लेन का अंडरपास, ट्रैफिक और प्रदूषण कम होने की उम्मीद

इस अंडरपास की एक और खास बात यह है कि इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह 6-लेन का है यानी एक साथ छह गाड़ियां इसमें से गुजर सकती हैं। साथ ही इसके दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई गई है ताकि लोकल ट्रैफिक को कोई परेशानी न हो। बरसात के पानी की निकासी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि अंडरपास में पानी न भरे। लाइटिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि रात के समय भी लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गौर चौक पर ट्रैफिक का दबाव लगभग 70 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। अभी जहां चौराहे पर पीक आवर में गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हैं, वहीं अंडरपास खुलने के बाद लंबी दूरी जाने वाले वाहन सीधे अंडरपास से निकल जाएंगे और केवल लोकल ट्रैफिक ही चौराहे पर रहेगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि पेट्रोल-डीजल की भी बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा।

यह अंडरपास केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विकास की एक नई कहानी है। कभी इस इलाके को बिल्डरों का फंसा हुआ प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन आज यहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। चाहे वह 130 मीटर रोड हो, मेट्रो का विस्तार हो या अब यह अंडरपास हो, हर प्रोजेक्ट इस इलाके को एनसीआर के सबसे बेहतर इलाकों में से एक बना रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि आने वाले दो सालों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई और बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे जिससे यहां रहने वाले लोगों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।







उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक भाषा और रणनीति में बदलाव करते दिखाई दे रहे हैं। कभी सामाजिक न्याय और पिछड़े, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाने वाले अखिलेश अब समाजवाद को सनातन और रामराज्य से जोड़कर पेश कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवाद ही रामराज्य है और सत्य, न्याय तथा दूसरों का सम्मान करने वाले लोग ही सच्चे सनातनी हैं। इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि जो सनातन है, वही समाजवाद है। उनके इन बयानों को 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से भाजपा के आरोपों का सामना करती रही है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को प्राथमिकता देती है और हिंदू हितों के मुद्दों पर पीछे रहती है। इस राजनीतिक छवि की जड़ें मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल तक जाती हैं, जब 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस की गोलीबारी की घटना के बाद भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया था। समय के साथ यह मुद्दा सपा की राजनीति से जुड़ गया। अब अखिलेश यादव रामराज्य, सनातन और धार्मिक आस्था की भाषा अपनाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और हिंदू परंपराएं एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ऐसे में उनका नया रुख केवल भाषणों का बदलाव नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दायरा बढ़ाने की कोशिश भी माना जा रहा है।

अखिलेश यादव की रणनीति को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के पिछले चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालना जरूरी है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे सहयोगियों के साथ सपा ने 111 सीटें जीतीं, लेकिन सरकार बनाने से दूर रह गई। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया और सपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नतीजे ने अखिलेश को यह भरोसा दिया कि पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। इसी आधार पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों का नारा उनकी राजनीति का अहम हिस्सा बना। लेकिन 2027 में सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल इसी सामाजिक समीकरण पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता। भाजपा का मजबूत हिंदू मतदाता आधार सपा के सामने बड़ी चुनौती है। इसलिए अखिलेश अब ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और समान अधिकारों को भी महत्व देते हैं। पूजा-पाठ से जुड़ी तस्वीरें साझा करना, भगवान श्रीकृष्ण से अपने संबंध का उल्लेख करना और रामराज्य की चर्चा करना इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

इस बदलाव में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े घटनाक्रम ने भी भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव ने उनके विचारों और भाजपा सरकार पर उठाए गए सवालों का सहारा लेकर धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रयागराज में कुंभ के दौरान शंकराचार्य और उनके साथ आए लोगों से जुड़े विवाद पर भी सपा अध्यक्ष ने सरकार को घेरा था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मुद्दों और धार्मिक व्यवस्थाओं पर उनके बयानों ने राजनीतिक बहस को और तेज किया। अखिलेश अब भाजपा पर सवाल उठाते हुए यह तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म का अर्थ केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और सम्मान के रास्ते पर चलना भी है। उनके मुताबिक, दूसरों को न्याय दिलाना और समाज में अच्छाई को बढ़ावा देना सनातन के मूल विचारों से जुड़ा है। भाजपा की ओर से हालांकि इस रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश के बयानों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सपा की सरकार में हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाई गईं और पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। भाजपा का कहना है कि अखिलेश के नए बयान उनकी पुरानी राजनीतिक छवि को नहीं बदल सकते। इस तरह रामराज्य और सनातन को लेकर दोनों दलों के बीच वैचारिक बहस अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है।

2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की इस बदली हुई राजनीति का असर कितना होगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं और दलित समाज के एक हिस्से का समर्थन मिला था। अब अखिलेश के सामने चुनौती है कि वह इस समर्थन को बनाए रखते हुए दूसरे हिंदू मतदाताओं के बीच भी अपनी जगह मजबूत करें। इसके लिए उन्हें केवल धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर भी भरोसा कायम करना होगा। दूसरी ओर भाजपा अपनी हिंदुत्व की राजनीति और सरकार के कामकाज को आधार बनाकर सपा के नए रुख पर सवाल उठाती रहेगी। चुनाव में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि पीडीए का सामाजिक समीकरण कितना मजबूत रहता है और क्या सपा अपने पुराने समर्थकों के साथ नए मतदाताओं को जोड़ पाती है। अखिलेश यादव की कोशिश समाजवाद को रामराज्य और सनातन से जोड़कर राजनीतिक बहस की दिशा बदलने की है। लेकिन इस रणनीति की असली परीक्षा चुनाव के दौरान होगी, जब मतदाता बयानों के साथ-साथ दलों के काम, उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों के आधार पर फैसला करेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भरोसे की भी होने जा रही है।



दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली के कई इलाकों तक हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ लोगों को सांस लेने में परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जहरीली हवा से बचने के लिए कौन-सा मास्क सबसे प्रभावी है? क्या सामान्य कपड़े या सर्जिकल मास्क पर्याप्त हैं, या फिर N95 जैसे रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा? आइए जानते हैं कि प्रदूषण के मौसम में मास्क खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दिल्ली से ग्रेटर नोएडा तक बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता

दिल्ली-NCR के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ने से प्रदूषण की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के आनंद विहार में AQI 300 के पार और जहांगीरपुरी में 350 तक दर्ज किया गया। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निगरानी आंकड़ों में राजधानी के कई स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की बात सामने आई।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में ग्रेटर नोएडा का AQI 346 तक दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले शहर का AQI 219 दर्ज किया गया था। प्रदूषण के साथ धुंध और स्मॉग के कारण दृश्यता प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ जाती है।

वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कदम उठाए जाते हैं। प्रदूषण का बढ़ता स्तर न केवल बाहर काम करने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है, बल्कि रोजाना दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, दोपहिया वाहन चालकों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी जोखिम बढ़ाता है।

मास्क खरीदते समय फिल्टरेशन और फिटिंग पर दें ध्यान

प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क खरीदते समय केवल उसकी कीमत, डिजाइन या ब्रांड पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्क हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने में कितना सक्षम है और वह चेहरे पर कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है।

शहरी प्रदूषण में मौजूद PM2.5 जैसे बेहद छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसा रेस्पिरेटर चुनना बेहतर होता है, जो इन कणों को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने के लिए प्रमाणित हो। मास्क नाक, मुंह और ठुड्डी को अच्छी तरह ढकना चाहिए। यदि किनारों से हवा अंदर जा रही है, तो उसकी सुरक्षा क्षमता कम हो सकती है।

इसके अलावा, ऐसा मास्क चुनना जरूरी है जिसे लंबे समय तक आराम से पहना जा सके। मास्क का सही आकार, चेहरे पर उसकी फिटिंग और निर्माता के निर्देशों का पालन उसकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



कपड़े और सर्जिकल मास्क से क्यों नहीं मिलता पर्याप्त बचाव?

कपड़े से बने सामान्य मास्क और सर्जिकल मास्क रोजमर्रा की कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से बचाव के लिए इन पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है।

कपड़े के मास्क की फिल्टर करने की क्षमता उसके कपड़े, परतों और बनावट पर निर्भर करती है। वहीं, सर्जिकल मास्क आमतौर पर चेहरे पर पूरी तरह सील नहीं बनाते। इनके किनारों से बिना फिल्टर हुई हवा अंदर पहुंच सकती है। यही वजह है कि प्रदूषण के उच्च स्तर पर ये प्रमाणित रेस्पिरेटर के मुकाबले कम प्रभावी हो सकते हैं।

इसलिए केवल मुंह ढकने के बजाय ऐसा मास्क चुनना अधिक उपयोगी है, जो सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए बनाया गया हो और चेहरे पर सही तरीके से फिट बैठता हो।

N95, KN95 और FFP2 में से कौन-सा मास्क चुनें?

प्रदूषण से बचाव के लिए N95, KN95 और FFP2 जैसे प्रमाणित रेस्पिरेटर बेहतर विकल्प माने जाते हैं। निर्धारित मानकों के अनुरूप बने ये मास्क सही फिटिंग और इस्तेमाल के साथ हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के संपर्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि, इनकी प्रभावशीलता मास्क की गुणवत्ता, प्रमाणन और चेहरे पर फिटिंग पर निर्भर करती है।



N95 मास्क: सही तरीके से पहने जाने पर यह हवा में मौजूद कम से कम 95 प्रतिशत परीक्षण-आधारित कणों को फिल्टर करने के लिए बनाया जाता है। रोजाना सड़क पर सफर करने वाले, ट्रैफिक के बीच काम करने वाले और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह उपयोगी विकल्प हो सकता है।

KN95 और FFP2 मास्क: ये भी सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए निर्धारित मानकों के तहत बनाए जाते हैं। इन्हें खरीदते समय प्रमाणन, गुणवत्ता और चेहरे पर फिटिंग की जांच करना जरूरी है।

N99 मास्क: यह उच्च फिल्ट्रेशन क्षमता वाला विकल्प है, जो निर्धारित परीक्षण परिस्थितियों में कम से कम 99 प्रतिशत कणों को फिल्टर करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि, केवल अधिक फिल्ट्रेशन रेट होने से यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए यही सबसे बेहतर विकल्प हो। सही फिटिंग और आराम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

दफ्तर जाने वाले लोग प्रमाणित रीयूजेबल रेस्पिरेटर भी चुन सकते हैं, बशर्ते उनके फिल्टर को निर्माता के निर्देशों के अनुसार बदला जाए और मास्क की नियमित सफाई तथा रखरखाव किया जाए। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने या बदलने के मामले में भी निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए।



मास्क के साथ इन सावधानियों को भी न करें नजरअंदाज

प्रदूषण से बचाव के लिए केवल मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है। AQI बेहद खराब होने पर खुले में व्यायाम और अनावश्यक गतिविधियों को कम करना, अधिक प्रदूषण वाले रास्तों से बचना और घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना भी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर उपयुक्त एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अस्थमा या सांस की दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। छोटे बच्चों पर रेस्पिरेटर के इस्तेमाल को लेकर भी उम्र और फिटिंग से संबंधित निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के दौरान प्रमाणित N95, KN95 या FFP2 रेस्पिरेटर सही फिटिंग के साथ सामान्य कपड़े और सर्जिकल मास्क से बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। हालांकि, कोई भी मास्क प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इसलिए सही मास्क के इस्तेमाल के साथ प्रदूषित हवा के संपर्क को कम करना ही बचाव की सबसे बेहतर रणनीति है।







साजिद अली
विशेष संवाददाता

दिल्ली-NCR में सर्दियों से पहले ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। नोएडा का AQI 249 के आसपास दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह 219 रहा। नोएडा की हवा खराब श्रेणी में है, जबकि ग्रेटर नोएडा की हवा भी खराब श्रेणी में आती है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-1 लागू कर दिया है। इसी बीच RTI से सामने आए आंकड़ों ने प्रदूषण फैलाने वालों पर लगाए गए जुर्माने और उनकी वसूली की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करीब 34 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय जुर्माने लगाए हैं, लेकिन वसूली की स्थिति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

GRAP-1 लागू, धूल और कचरा जलाने पर सख्ती

GRAP प्रदूषण बढ़ने पर लागू किया जाने वाला चरणबद्ध एक्शन प्लान है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ नियंत्रण के उपाय बढ़ाए जाते हैं। पहले चरण यानी स्टेज-1 का संबंध खराब श्रेणी की हवा से है, जिसमें AQI 201 से 300 के बीच होता है। यह व्यवस्था पूरे NCR में लागू की गई है, इसलिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी संबंधित एजेंसियों को निर्देशों का पालन कराना होगा।

स्टेज-1 के तहत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना, निर्माण सामग्री और मलबे को ढककर रखना, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाना तथा सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव सुनिश्चित करना शामिल है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का उचित निस्तारण भी जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाली साइटों और संस्थानों के खिलाफ संबंधित कानूनों और निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

₹34 करोड़ के जुर्माने, वसूली की स्थिति पर सवाल

प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के दावों के बीच जुर्माने की वसूली का मुद्दा गंभीर है। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता की RTI के जवाब में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों के लिए करीब 34 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय जुर्माने लगाए गए हैं। इनमें निर्माण गतिविधियों, कचरा जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल हैं।

हालांकि, बोर्ड के RTI जवाब में जुर्माने की वसूली का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कुल लगाए गए जुर्माने में से कितनी रकम वास्तव में जमा हुई। पहले के एक RTI जवाब में करीब 26.94 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा नहीं होने का उल्लेख भी किया गया था। लेकिन अलग-अलग जवाबों और समयावधियों के आंकड़ों को मिलाकर यह दावा करना उचित नहीं होगा कि कुल जुर्माने का केवल 3 प्रतिशत ही वसूला गया है।

यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि जुर्माना लगाने के बाद उसकी वसूली और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यदि दंड की रकम लंबे समय तक लंबित रहती है, तो प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई का असर कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट करना और लंबित मामलों की निगरानी जरूरी है।

प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण बढ़ने के पीछे सड़क और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां अहम कारण हो सकती हैं। सर्दियों की शुरुआत में हवा की गति कम होने और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषक वातावरण में जमा हो सकते हैं। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी मौसम और हवा की दिशा के आधार पर NCR की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, किसी खास दिन प्रदूषण बढ़ने के पीछे किस स्रोत की कितनी भूमिका रही, यह जानने के लिए संबंधित आंकड़ों और वैज्ञानिक आकलन की जरूरत होती है। इसलिए प्रदूषण के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराने के बजाय स्थानीय उत्सर्जन और मौसम, दोनों पर ध्यान देना जरूरी है।

AQI और बिगड़ा तो बढ़ सकती हैं पाबंदियां

GRAP के तहत AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर स्टेज-2 के उपाय लागू किए जाते हैं। इसमें धूल और प्रदूषण पर नियंत्रण के अतिरिक्त उपायों के साथ डीजल जनरेटर के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करना और निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अगला चरण कब लागू होगा, यह केवल अनुमान से तय नहीं होता। CAQM संबंधित AQI, मौसम के पूर्वानुमान और प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला लेता है।

नागरिक भी प्रदूषण कम करने में योगदान दे सकते हैं। खुले में कचरा न जलाएं, निजी वाहन की जगह संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और अपने आसपास निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों पर ध्यान दें। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों को खराब हवा में लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP लागू करना जरूरी कदम है, लेकिन इसका वास्तविक असर नियमित निगरानी, नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई और जुर्माने की पारदर्शी वसूली पर निर्भर करेगा।





अभिषेक पांडेय
विशेष संवाददाता

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना यानी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर सियासी बहस तेज है। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव घटेगा और विकास कार्यों में बार-बार आने वाली रुकावटें कम होंगी। वहीं, विपक्ष इसे राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे के लिए चुनौती बता रहा है। हालांकि, एक अहम तथ्य यह है कि संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 अभी संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। इसे 9 अक्टूबर 2026 को लोकसभा से पास किए जाने का दावा सही नहीं है। ऐसे में 2029 में एक साथ चुनाव होना फिलहाल संभावित लक्ष्य है, कोई अंतिम फैसला नहीं।

क्या है वन नेशन, वन इलेक्शन का प्लान?

इस योजना का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराना है। इसके लिए दिसंबर 2024 में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित एक अन्य विधेयक संसद में पेश किया गया था। दोनों विधेयकों को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया।

प्रस्तावित व्यवस्था में संविधान का अनुच्छेद 82A जोड़ने और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की बात है। इसके तहत चुनावी चक्र को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग होती है, तो वहां चुनाव कराए जाने के बाद नई विधानसभा का कार्यकाल साझा चुनावी चक्र के शेष समय तक सीमित रह सकता है। इससे अगली बार सभी चुनाव एक साथ कराने का रास्ता तैयार होगा, लेकिन सरकारों के कार्यकाल में बदलाव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

सरकार का तर्क: खर्च घटेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार

सरकार का कहना है कि बार-बार चुनाव कराने में चुनाव आयोग, प्रशासन, सुरक्षा बलों और राजनीतिक दलों को भारी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। एक साथ चुनाव होने से इन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा, चुनाव के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण कुछ नई घोषणाओं और नीतिगत फैसलों पर सीमाएं लगती हैं। सरकार का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को एक चक्र में लाने से प्रशासनिक कामकाज अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने 191 दिनों तक विचार-विमर्श किया और 47 राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त किए। इनमें से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की थी। हालांकि, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

विपक्ष की चिंता: राज्यों की राजनीति पर पड़ेगा असर?

विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों की प्रमुख चिंता यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे विषय अहम होते हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में रोजगार, बिजली, पानी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। आलोचकों को आशंका है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर मतदाताओं के व्यवहार और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों की खरीद, भंडारण, परिवहन और सुरक्षा के साथ-साथ चुनावी कर्मचारियों की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए केवल राजनीतिक सहमति ही नहीं, बल्कि पर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक तैयारी भी चाहिए।

2029 का रोडमैप: अभी बाकी हैं कई पड़ाव

संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और लागू होने से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राज्यों की मंजूरी की जरूरत का सवाल भी तय होगा। फिलहाल विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास है, इसलिए इसे संसद से पारित या कानून बन चुका बताना सही नहीं होगा।

अब सवाल यही है कि क्या 2029 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो पाएंगे? यह प्रस्तावित लक्ष्य जरूर है, लेकिन इसके लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट, संसद में विधेयकों का पारित होना, आवश्यक संवैधानिक मंजूरियां और चुनाव आयोग की तैयारियां अहम होंगी। फिलहाल वन नेशन, वन इलेक्शन पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है। आने वाले समय में होने वाली संसदीय कार्रवाई ही तय करेगी कि यह योजना कब और किस रूप में लागू हो सकती है।





ऋषभ कांत छाबड़ा
विशेष संवाददाता

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ विवाद अब चुनाव आयोग, विपक्ष, युवा आंदोलनकारियों और अदालत के बीच बड़ी लड़ाई बन चुका है. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के आंदोलन ने इस विवाद को नई पहचान दी है। विपक्ष ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को सही करना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि SIR आखिर क्या है, दिल्ली में बवाल क्यों हुआ और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?

SIR क्या है और विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की विस्तृत जांच करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मृत मतदाताओं के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियां ठीक करना, दूसरी जगह स्थायी रूप से जा चुके लोगों के रिकॉर्ड दुरुस्त करना और पात्र मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करना है। चुनाव आयोग के मुताबिक, सही मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और कई नागरिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दस्तावेजों की जांच और नामों को हटाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी हुई, तो गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बार-बार जगह बदलने वाले लोगों के नाम छूट सकते हैं। विवाद इसलिए गंभीर है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम न होने पर कोई पात्र नागरिक चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकता है। आलोचक चाहते हैं कि हर नाम हटाने के पीछे स्पष्ट कारण हो और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले।

कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को कैसे दी धार?

इस विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का नाम तेजी से चर्चा में आया। यह युवाओं का ऐसा आंदोलन है, जिसने व्यंग्य और विरोध के जरिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आंदोलन से जुड़े लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR की प्रक्रिया रोकने की मांग की। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने से लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इस आंदोलन को केवल राजनीतिक दलों का विरोध नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और मताधिकार से जुड़ी लड़ाई के रूप में पेश किया गया।

अक्टूबर में दिल्ली और मुंबई में हुए प्रदर्शनों में युवा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। 3 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर आई। आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों का हवाला देते हुए मतदान के अधिकार की अहमियत बताई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही तय करे और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से न हटाए।

दिल्ली में मेट्रो बंद, प्रदर्शनकारियों की धरपकड़

10 अक्टूबर को दिल्ली में आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR को लेकर जवाबदेही की मांग करना था। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया। कई रिपोर्टों के मुताबिक, उस दिन दो हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और मध्य दिल्ली के करीब 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की खबर सामने आई। इससे आम यात्रियों को भी परेशानी हुई। पुलिस का पक्ष था कि संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई। पत्रकारों और वकीलों के काम में बाधा, लोगों को हिरासत में लेने और सार्वजनिक परिवहन रोकने जैसे मुद्दे भी अदालत तक पहुंचे। इस तरह मतदाता सूची का विवाद केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार और आम नागरिकों की आवाजाही का सवाल भी बन गया।

CJP नेताओं की गिरफ्तारी और रिहाई से बढ़ा विवाद

आंदोलन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े नेताओं सौरव दास और



आशुतोष रंका को भी गिरफ्तार किया गया। वे करीब एक सप्ताह तक तिहाड़ जेल में रहे। बाद में एक विशेष मजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। रिहाई के दौरान उन्हें शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ीं। आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियों और हिरासत के जरिए आंदोलनकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही। पुलिस ने दूसरी ओर प्रदर्शन की अनुमति, बैरिकेड तोड़ने और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े आरोपों के आधार पर कार्रवाई का बचाव किया। इस घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की सीमा क्या होनी चाहिए और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस हद तक प्रतिबंध लगा सकता है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे मताधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी सार्वजनिक सुरक्षा और सामान्य जनजीवन बनाए रखना भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या निर्देश दिए?

दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने इसे गंभीरता से लिया। 11 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए, मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चलें और इंटरनेट जैसी सुविधाओं पर रोक कानून के मुताबिक ही लगाई जाए। अदालत ने पत्रकारों और वकीलों को अपना काम करने देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने पर भी जोर दिया। दिल्ली प्रशासन से मेट्रो स्टेशन बंद करने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के मामले में जवाब मांगा गया।

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने SIR में कथित गड़बड़ियों, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर चुनाव आयोग तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। अदालत ने इस स्तर पर SIR पर देशव्यापी रोक नहीं लगाई, बल्कि संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं, पत्रकारों की सुरक्षा और दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका पर दबाव डालकर फैसले नहीं कराए जा सकते।

विपक्ष की लड़ाई और चुनाव आयोग का पक्ष

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी पात्र मतदाता को अपनी नागरिक पहचान या मतदान का अधिकार साबित करने के लिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और नाम हटाने के नियमों की समीक्षा की मांग की। विपक्ष के कुछ नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसका मकसद सूची को सही बनाना है। आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना है कि गलत प्रविष्टियां हटाने के साथ किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे।

अब आगे क्या हो सकता है?

आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, चुनाव आयोग के जवाब और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अदालत यह तय कर सकती है कि मतदाताओं को नोटिस देने, आपत्तियों की सुनवाई और नाम हटाने की प्रक्रिया में कौन-सी अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी है। दूसरी ओर दिल्ली में आंदोलन भी जारी रहने के संकेत हैं। 23 अक्टूबर को 'पीपल अगेंस्ट SIR' नाम के नागरिक समूह के प्रदर्शन के दौरान भी 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इस समूह को कॉकरोच जनता पार्टी से अलग पहचानना जरूरी है, हालांकि दोनों ही SIR और चुनाव आयोग की जवाबदेही को लेकर विरोध कर रहे हैं। SIR की बहस अब सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं रह गई है। यह मताधिकार, चुनाव आयोग की जवाबदेही और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। मतदाता सूची को दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई पात्र नागरिक केवल दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक गलती के कारण वोट देने के अधिकार से वंचित न हो। यही आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद की सबसे अहम कसौटी होगी।



अयोध्या के राम, ग्रेटर नोएडा में धाम

ईकोटेक-12 में 5 लाख लोगों ने देखा 85 फुट रावण का अंत







ईकोटेक-12 का दशहरा इस बार सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए एक नया इतिहास बन गया। 20 अक्टूबर 2026 की वह शाम जब लगभग पाँच लाख लोग एक ही मैदान में इकट्ठा हुए, तो ऐसा लगा जैसे पूरा एनसीआर एक जगह पर सिमट आया हो। कभी यह इलाका सिर्फ ऊँची-ऊँची सोसाइटियों और निर्माणाधीन इमारतों के लिए जाना जाता था, पर उस शाम उसने खुद को एनसीआर की नई सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया। इस आयोजन के पीछे 45 दिनों की कड़ी मेहनत थी। मेरठ और मुरादाबाद से तीस विशेष कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके 85 फुट ऊँचा रावण, 75 फुट का कुंभकरण और 70 फुट का मेघनाद तैयार किया था। ये पुतले सिर्फ बांस और कागज से नहीं बने थे, बल्कि इनमें पर्यावरण के अनुकूल आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया था ताकि प्रदूषण कम से कम हो।



अयोध्या के राम मंदिर की थीम और राम-रावण युद्ध का मंचन

इस साल की थीम रखी गई थी अयोध्या के राम, ग्रेटर नोएडा में धाम। इसी थीम के अनुसार मैदान के मुख्य प्रवेश द्वार को चालीस फुट ऊँचा अयोध्या राम मंदिर के मॉडल जैसा बनाया गया था, जिस पर फूलों और रोशनी की ऐसी सजावट थी कि लोग वहाँ सेल्फी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। दोपहर दो बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। तीन बजे तक मैदान के आसपास की सभी सड़कें जाम हो गईं और कई सोसाइटियों ने तो अपने निवासियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी चलाई थी। शाम पाँच बजे तक मैदान में तिल रखने की जगह नहीं बची थी और पुलिस के ड्रोन कैमरे भीड़ की निगरानी कर रहे थे। शाम छह बजे रामलीला के अंतिम अध्याय राम-रावण युद्ध का मंचन शुरू हुआ तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। छोटे-छोटे बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। वह दृश्य ऐसा था कि हर किसी की आँखें मंच पर ही टिकी हुई थीं।

ठीक आठ बजकर पंद्रह मिनट पर पंडित जी के मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ भगवान राम के स्वरूप ने अग्नि-बाण छोड़ा और एक साथ तीनों पुतले धू-धू कर जल उठे। पटाखों की गड़गड़ाहट दो किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी और पूरा मैदान जय श्री राम के जयकारों से गूँज उठा। लोगों ने अपने मोबाइल से इस पल को कैद करना शुरू कर दिया।जैसे ही रावण आधा जल गया, अचानक आकाश में तीन सौ ड्रोन एक साथ उड़े और उन्होंने लाइटों से पहले जय श्री राम लिखा, फिर भगवान राम का धनुष-बाण बनाया और अंत में अयोध्या के राम मंदिर की पूरी आकृति बना दी। यह दृश्य देखकर कई बुजुर्गों की आँखों में आँसू आ गए और लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर पूरे मैदान को जगमगा दिया। यह संगम था परंपरा और तकनीक का, आस्था और आधुनिकता का।

250 से ज्यादा स्टॉल, देशभर के व्यंजन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

रावण दहन के अलावा मैदान में लगा मेला भी अपने आप में पूरे भारत का दर्शन था। वहाँ ढाई सौ से अधिक स्टॉल लगे थे जहाँ बिहार की लिट्टी-चोखा से लेकर राजस्थान की दाल-बाटी चूरमा, पंजाब के छोले-भटूरे, मुंबई की पाव-भाजी और बंगाल के रसगुल्ले तक सब कुछ मिल रहा था। खरीदारी के लिए बनारस की साड़ियाँ, जयपुर की जूतियाँ और उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे थे और बच्चों के लिए बीस से अधिक बड़े झूले लगे थे।

इतनी बड़ी भीड़ में अक्सर भगदड़ का डर रहता है पर इस बार व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि सभी ने तारीफ की। गौतमबुद्ध नगर पुलिस के डेढ़ सौ से अधिक जवान, दो सौ निजी बाउंसर और चालीस हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे पूरे मैदान की निगरानी कर रहे थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए थे, पीने के पानी के दस बड़े टैंकर, बीस मोबाइल टॉयलेट और पाँच मेडिकल वैन तैनात थीं और सबसे बड़ी बात पूरा कार्यक्रम प्लास्टिक-मुक्त रखा गया था।

स्थानीय लोगों में उत्साह, अगले साल और भव्य आयोजन का वादा

स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह था। ईकोटेक-12 में रहने वाले अमित सिंह कहते हैं कि वे 2014 से यहाँ रह रहे हैं और पहले यहाँ कुछ नहीं था पर आज यहाँ पाँच लाख लोग आ रहे हैं जो गर्व की बात है। पंचशील ग्रीन सोसाइटी की रीना देवी कहती हैं कि पहले दशहरे पर उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था पर अब वे गर्व से कहती हैं कि आओ हमारा ईकोटेक-12 देखो। आयोजन समिति ने अगले साल सौ फुट से भी ऊँचा रावण और पंद्रह दिन तक चलने वाली भव्य रामलीला का वादा किया है।सच में यह दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह इस बात का ऐलान था कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट अब केवल इमारतों का शहर नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और एकता का नया केंद्र बन चुका है और आने वाले वर्षों में यह एनसीआर का सबसे बड़ा दशहरा हब बनने जा रहा है।



ग्रेटर नोएडा। दिल्ली-NCR में नशीले पदार्थों की कथित तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की आगरा जोन इकाई ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 920 ग्राम MDMA बरामद हुई है, जिसकी अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने एक स्कूटी भी जब्त की है। शुरुआती जांच में इस मामले के तार दिल्ली से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। यह कार्रवाई 19 अक्टूबर 2026 को नॉलेज पार्क-II मेट्रो स्टेशन के पास की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घाना के नागरिक उसुलोर और उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर की निवासी लायलो शरजाय के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों कथित तौर पर नशीले पदार्थों की बिक्री और सप्लाई से जुड़े थे। हालांकि, नेटवर्क में उनकी वास्तविक भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

गुप्त सूचना पर बिछाया गया जाल

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक विदेशी नागरिक नशीले पदार्थों की खेप लेकर नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास आने वाला है और वहां एक महिला को इसकी डिलीवरी दी जानी है। इसके बाद नॉलेज पार्क थाना पुलिस और ANTF की आगरा जोन इकाई ने संयुक्त अभियान चलाया। निगरानी के दौरान संदिग्धों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, जिसमें 920 ग्राम MDMA बरामद होने की जानकारी दी गई। MDMA एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव पदार्थ है, जिसे आमतौर पर एक्स्टेसी भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ लोग पार्टी ड्रग के रूप में करते हैं, लेकिन इसके सेवन से शरीर का तापमान बढ़ने, हृदय गति तेज होने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है। पुलिस के अनुसार, उसुलोर दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में रह रहा था, जबकि लायलो शरजाय के दिल्ली और लखनऊ से जुड़े पते सामने आए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों पासपोर्ट और वीजा संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। उनके भारत में प्रवेश और प्रवास की स्थिति की जांच की जा रही है। हालांकि, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना अपने आप में अवैध प्रवास का अंतिम प्रमाण नहीं है।

दिल्ली में कथित सप्लायर की तलाश

पुलिस की शुरुआती जांच में कलिस्टो नाम के एक व्यक्ति का जिक्र सामने आया है। पुलिस के अनुसार, वह कथित तौर पर MDMA तैयार करता था और गिरफ्तार आरोपी इसकी बिक्री में शामिल थे। अधिकारियों ने उसे पकड़ने के प्रयास किए जाने की जानकारी दी है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नशीला पदार्थ कहां तैयार किया गया, इसे कहां से हासिल किया गया और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक होनी थी। दिल्ली-NCR और आगरा से जुड़े संभावित संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और कथित सप्लाई नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद खेप का अंतिम खरीदार कौन था या इसे किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय अथवा पार्टी में पहुंचाने की योजना थी। इन संभावनाओं की पुष्टि के लिए जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा।

NDPS एक्ट के तहत मुकदमा, जांच जारी

इस मामले में थाना नॉलेज पार्क में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों में धारा 8A(C), 22(C), 29 और 60 का उल्लेख है। पुलिस ने मामले में अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी है। धाराओं और कानूनी प्रक्रिया की अंतिम पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क क्षेत्र कई कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और छात्रावासों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहां नशीले पदार्थों की कथित सप्लाई का मामला पुलिस के लिए गंभीर जांच का विषय है। हालांकि, इस बरामदगी के आधार पर किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान या छात्र समूह को इस नेटवर्क से जोड़ने का कोई पुष्ट आधार सामने नहीं आया है। पुलिस अब बरामद MDMA के स्रोत, आरोपियों के संपर्कों और कथित सप्लायर की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। कलिस्टो की गिरफ्तारी और आगे की जांच से नेटवर्क के विस्तार तथा अन्य संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।





कैंसर का इलाज कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 137 नॉन-शेड्यूल कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा 30 प्रतिशत तय कर दी है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) के इस फैसले से इन दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी MRP में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि, कीमतों में वास्तविक कमी हर दवा की मौजूदा कीमत और उसके ट्रेड मार्जिन पर निर्भर करेगी।

137 दवाओं पर क्यों लगी ट्रेड मार्जिन की सीमा?

NPPA ने पाया कि कुछ नॉन-शेड्यूल कैंसर दवाओं की सप्लाई चेन में ट्रेड मार्कअप काफी अधिक था। कुछ दवाओं पर यह औसतन करीब 170 प्रतिशत और चुनिंदा मामलों में 700 प्रतिशत तक पहुंच रहा था। ऐसे में सरकार ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत हस्तक्षेप किया है। यह प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में जनहित को ध्यान में रखते हुए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

नई व्यवस्था में ट्रेड मार्जिन की सीमा MRP पर GST को छोड़कर 30 प्रतिशत तय की गई है। यह स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर को दवा की बिक्री कीमत के मुकाबले लगभग 42.86 प्रतिशत मार्कअप के बराबर है। इसका मकसद दवा बनाने वाली कंपनी की कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली कीमत के बीच अत्यधिक अंतर को कम करना है।

निर्माताओं को अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर NPPA को संशोधित कीमतों की जानकारी देनी है। उन्हें नई कीमतें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और मेडिकल स्टोर, अस्पतालों तथा अन्य संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को भी नई दरें लागू होने पर संशोधित कीमतों का पालन करना होगा। कंपनियों को दवाओं का मौजूदा उत्पादन और सप्लाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कीमत घटने के कारण मरीजों को दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े।

इम्यूनोथेरेपी से लेकर दूसरी कैंसर दवाएं भी शामिल

इस सूची में कई महत्वपूर्ण कैंसर दवाएं शामिल हैं। इनमें Pembrolizumab, Durvalumab और Osimertinib जैसी दवाएं हैं, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के कुछ मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली Denosumab, कैंसर मरीजों में न्यूट्रोपेनिया का जोखिम कम करने के लिए दी जाने वाली Pegfilgrastim और कुछ प्रकार के कोलन, ओवेरियन तथा सर्वाइकल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Bevacizumab भी इस सूची का हिस्सा हैं।

इन दवाओं का चयन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। सूची में ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जो पहले सामान्य मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत निर्धारित कीमतों की सीमा में नहीं आती थीं। हालांकि, किसी दवा की कीमत कितनी घटेगी, यह उसकी मौजूदा MRP, कंपनी की बिक्री कीमत और निर्धारित गणना के आधार पर तय होगा। जिन दवाओं की मौजूदा MRP नई गणना से कम है, उनकी कीमत बढ़ाने के बजाय पुरानी कम कीमत बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

2019 में भी हुआ था ऐसा प्रयोग, अब आगे बढ़ी योजना

कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन नियंत्रित करने का यह पहला प्रयास नहीं है। वर्ष 2019 में सरकार ने 42 कैंसर दवाओं के लिए इसी तरह की व्यवस्था लागू की थी। उस पहल के बाद 526 ब्रांड की नॉन-शेड्यूल कैंसर दवाओं की MRP में 90 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई थी। उस समय मरीजों को लगभग 984 करोड़ रुपये की सालाना बचत होने का अनुमान सामने आया था। अब सरकार ने इस मॉडल को 137 दवाओं तक विस्तारित किया है।

दवाओं की ऊंची कीमतों का मुद्दा हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। 29 सितंबर 2026 को दवाओं की कीमतों और सप्लाई चेन में भारी मार्कअप से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अंतर पर गंभीर चिंता जताई थी। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि मौजूदा फैसला केवल अदालत की टिप्पणी के कारण लिया गया। सरकार की नई व्यवस्था विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और NPPA की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के आधार पर लाई गई है।





इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा PHP में सुरक्षा की दो गंभीर खामियां सामने आने के बाद दुनियाभर में साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर हमलावर वेबसाइटों के सर्वर तक अनधिकृत पहुंच बनाने, संवेदनशील डेटा चुराने और ऑनलाइन सेवाओं को बाधित करने की कोशिश कर सकते थे। PHP का इस्तेमाल बड़ी संख्या में वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है, इसलिए इन खामियों का संभावित प्रभाव भी व्यापक था। खतरे को देखते हुए कई देशों में सरकारी और सार्वजनिक वेबसाइटों की जांच की गई, जबकि कुछ सेवाओं को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने नागरिकों को घर में तीन दिन यानी 72 घंटे तक काम आने वाला जरूरी सामान रखने की सलाह दी। हालांकि, यह सलाह केवल साइबर हमलों के लिए नहीं, बल्कि दूसरी आपात स्थितियों के लिए भी है। ऐसे में सवाल है कि PHP में मिली ये खामियां कितनी गंभीर थीं, AI ने इन्हें खोजने में क्या भूमिका निभाई और इंटरनेट की सुरक्षा के लिए आगे क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं?

PHP की दो खामियों ने क्यों बढ़ाई दुनिया की चिंता?

PHP एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के पीछे काम करने वाले सिस्टम को तैयार करने में किया जाता है। वर्डप्रेस, ड्रुपल और जूमला जैसे कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी PHP पर निर्भर करते हैं। वेबसाइटों में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का विश्लेषण करने वाली W3Techs के अनुमान के मुताबिक, जिन वेबसाइटों की तकनीक की पहचान की जा सकी, उनमें लगभग 69.3 प्रतिशत में PHP का इस्तेमाल होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इतनी ही वेबसाइटें इन खामियों से सीधे प्रभावित हुईं।

सुरक्षा संबंधी दोनों कमजोरियां कंप्यूटर की मेमोरी के प्रबंधन और प्रोग्राम में आने वाली गलतियों को संभालने की प्रक्रिया से जुड़ी थीं। इन कमियों का फायदा उठाकर हमलावर कुछ परिस्थितियों में वेबसाइट के सर्वर पर बिना अनुमति अपने निर्देश चलाने की कोशिश कर सकते थे। इससे सर्वर में मौजूद फाइलों, संवेदनशील जानकारियों और दूसरे डिजिटल संसाधनों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता था।

साइबर सुरक्षा कंपनी Hadrian ने इन कमजोरियों के संभावित दुरुपयोग से जुड़ी गतिविधियों को PHP2Shell नाम दिया। यहां शेल का मतलब ऐसे इंटरफेस से है, जिसके जरिए कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं। यदि किसी हमलावर को सर्वर पर इस तरह की पहुंच मिल जाती, तो वह सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करने या नेटवर्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था।

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) ने भी इन खामियों से जुड़े जोखिमों को लेकर चेतावनी दी। हालांकि, किसी सॉफ्टवेयर में गंभीर कमजोरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उससे जुड़ी हर वेबसाइट हैक हो गई। वास्तविक खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित सिस्टम प्रभावित संस्करण का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, उसमें सुरक्षा के दूसरे उपाय मौजूद हैं या नहीं और जरूरी अपडेट लगाए गए हैं या नहीं।



AI ने खोजीं कमजोरियां, लेकिन खुलासे से पहले ही बढ़ गया खतरा

इस पूरे मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका खास रही। PHP फाउंडेशन ने अपने कोड की जांच में AI आधारित उपकरणों की मदद ली। इस प्रक्रिया में एंथ्रोपिक के उन्नत AI मॉडल सहित दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। PHP को OpenAI के Patch the Planet कार्यक्रम में भी शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर की सुरक्षा कमजोरियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में शोधकर्ताओं की मदद करना है।

उपलब्ध घटनाक्रम के मुताबिक, साइबर सुरक्षा कंपनी Calif ने 30 जुलाई को PHP कोड की जांच शुरू की थी। इसके बाद शोधकर्ता Ryan N ने 11 अगस्त को एक गंभीर समस्या की जानकारी दी। OpenAI ने भी उसी दिन इससे जुड़ी एक समस्या की सूचना दी। बाद में साइबर सुरक्षा कंपनी Wiz ने 24 अगस्त को एक अन्य तरीके से कमजोरी का फायदा उठाए जाने की जानकारी दी।

AI बड़ी मात्रा में कोड का विश्लेषण करके उन हिस्सों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जहां सुरक्षा संबंधी गलतियां होने की आशंका है। इससे विशेषज्ञों को संभावित खामियों का पता लगाने में समय की बचत होती है। लेकिन किसी कमजोरी की पुष्टि करना, उसका प्रभाव समझना और सुरक्षित समाधान तैयार करना अब भी विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण काम है।

चिंता तब बढ़ी, जब खामियों से जुड़े पहचान नंबर निर्धारित सार्वजनिक खुलासे से दो दिन पहले इंटरनेट पर फैलने लगे। इसके बाद PHP की टीम ने सुरक्षा अपडेट जारी करने की तारीख एक दिन पहले कर दी। रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम के अनुसार, इन कमजोरियों की जानकारी 22 अक्टूबर को सार्वजनिक की जानी थी।

Amazon की साइबर खतरा खुफिया टीम ने भी आधिकारिक खुलासे से पहले 17 अक्टूबर को एक हमले की कोशिश दर्ज की थी। इसमें कंपनी के एक विशेष परीक्षण तंत्र को निशाना बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और हमलों के तरीकों का विश्लेषण करने के लिए होता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमलावरों को कमजोरियों की जानकारी पहले कैसे मिली। किसी हमले की कोशिश दर्ज होना अपने आप में सफल सेंधमारी का प्रमाण नहीं है।

कई देशों में वेबसाइटें बंद, ब्रिटेन की 72 घंटे की तैयारी क्यों अहम?

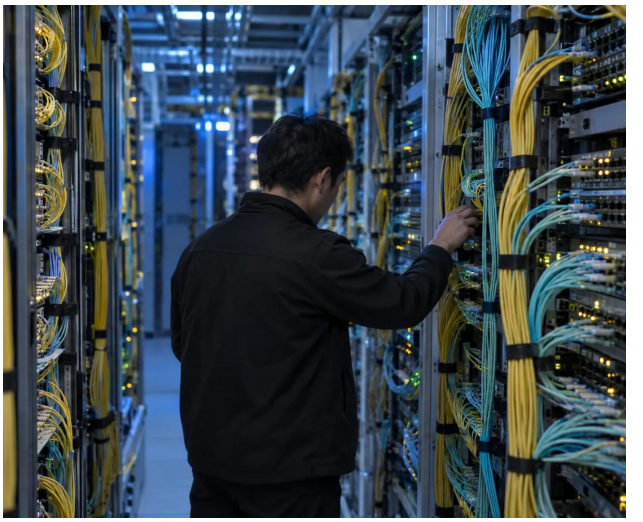
खामियों की जानकारी सामने आने के बाद कई देशों में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं ने अपने सिस्टम की जांच शुरू की। कुछ वेबसाइटों को सुरक्षा उपाय लागू करने और संभावित जोखिम कम करने के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया।

नीदरलैंड में रॉटरडैम बंदरगाह की वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट Overheid.nl और कुछ राजनीतिक दलों की वेबसाइटों सहित कई सार्वजनिक डिजिटल सेवाएं प्रभावित हुईं या एहतियातन बंद की गईं। डेनमार्क में Kombit ने स्कूलों के बीच संदेश भेजने से जुड़ी कुछ सेवाएं रोक दीं। फिनलैंड की Valtori ने कुछ सार्वजनिक नेटवर्क सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया। वहीं, फ्रांस के गृह मंत्रालय ने भी अपनी वेबसाइटों को रखरखाव के लिए बंद किया।

ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र (NCSC) ने 50 हजार से ज्यादा चेतावनी संदेश भेजे, ताकि वेबसाइट संचालक खतरे को समझकर जरूरी सुरक्षा कदम उठा सकें। सुरक्षा अपडेट लगाने और जांच पूरी करने के बाद कई संस्थानों ने अपनी सेवाएं फिर शुरू कीं।

इसी बीच ब्रिटेन सरकार की ओर से नागरिकों को घर में 72 घंटे तक काम आने वाला जरूरी सामान रखने की सलाह ने भी ध्यान खींचा। यह सलाह सरकार के 'Be Ready' अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी आपात स्थितियों के लिए तैयार करना है, जिनमें बिजली, संचार, परिवहन या रोजमर्रा की डिजिटल सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसमें गंभीर मौसम, दूसरी आपदाओं और अन्य संकटों की परिस्थितियां भी शामिल हैं।

आज बैंकिंग, खरीदारी, सरकारी सेवाओं, संचार और कई दूसरी सुविधाओं के लिए इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाएं बाधित होने से लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि, 72 घंटे की तैयारी की सलाह को केवल PHP की खामियों या किसी एक साइबर हमले से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। यह व्यापक आपातकालीन तैयारी का हिस्सा है।



क्या AI साइबर हमलों को और खतरनाक बना सकता है?

इस मामले ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में AI के दोहरे इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ AI की मदद से सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाना आसान और तेज हो सकता है। इससे कंपनियां और सरकारी संस्थाएं अपने सिस्टम को समय रहते सुरक्षित कर सकती हैं। दूसरी तरफ, हमलावर भी इसी तकनीक का इस्तेमाल संभावित कमजोरियां खोजने, हमले की तैयारी करने और सुरक्षा उपायों को चकमा देने के लिए कर सकते हैं।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह पता लगाना है कि किसी संगठन के कितने सर्वर और वेबसाइटें प्रभावित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़े संगठनों के पास कई पुराने और नए सिस्टम होते हैं। कई बार किसी सर्वर पर चल रहे सॉफ्टवेयर का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सभी प्रभावित सिस्टम की पहचान करना और उन पर समय रहते सुरक्षा अपडेट लगाना आसान नहीं होता।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने वेबसाइट संचालकों को सर्वर पर असामान्य गतिविधियों, बिना अनुमति चलाए गए निर्देशों और संदिग्ध नेटवर्क कनेक्शन पर नजर रखने की सलाह दी। जिन सिस्टम को तुरंत सुरक्षित करना संभव नहीं है, उन्हें जोखिम का आकलन करके अस्थायी रूप से बंद करना भी एक विकल्प हो सकता है।

इस मामले का एक अहम पहलू उन इंजीनियरों की सीमित संख्या है, जो PHP जैसी व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली तकनीक को सुरक्षित बनाए रखने में जुटे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, PHP फाउंडेशन के पास इस भाषा के रखरखाव के लिए केवल 13 पूर्णकालिक और अंशकालिक इंजीनियर हैं। इसके मुकाबले AI के विकास पर दुनिया भर में भारी निवेश किया जा रहा है। इससे सवाल उठता है कि इंटरनेट की बुनियादी तकनीकों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञ उपलब्ध कराने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है।

निष्कर्ष यह है कि PHP की सुरक्षा खामियों ने एक बार फिर दिखाया है कि इंटरनेट की सुरक्षा केवल किसी एक कंपनी या वेबसाइट की जिम्मेदारी नहीं है। एक लोकप्रिय तकनीक में मौजूद कमजोरी का असर दुनियाभर की सेवाओं तक पहुंच सकता है। AI कमजोरियों को खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सॉफ्टवेयर की नियमित जांच हो, सुरक्षा अपडेट समय पर लगाए जाएं और संस्थाएं आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें।



दिवाली का त्योहार आते ही बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, झालरों और पटाखों से सजने लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस त्योहार को खास बनाने की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन इसी उत्सव की चमक के पीछे पटाखों के निर्माण और भंडारण में बरती जाने वाली लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका भयावह उदाहरण बिहार के सीवान जिले में देखने को मिला। दिवाली से कुछ दिन पहले एक मकान में हुए भीषण विस्फोट ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिस घर में पटाखे तैयार किए जा रहे थे, वहां धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे ने त्योहार के मौसम में पटाखों की मांग, उनके कारोबार और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिवाली की तैयारी के बीच बारूद का कहर, पांच लोगों की मौत की पुष्टि

23 अक्टूबर की शाम बिहार के सीवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव में पटाखे बनाने के दौरान भीषण विस्फोट हुआ। जिस मकान में पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, वहां आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर सड़क की ओर गिर गया। घटनास्थल पर मलबा बिखर गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती घंटों में मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आईं, लेकिन जिला प्रशासन ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि की। दो अन्य लोगों के लापता होने की आशंका के बीच मलबे की तलाशी भी जारी रही। धमाके के बाद पटाखों में आग लगने और रुक-रुककर विस्फोट होने की वजह से बचाव दल को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की गई।

यह हादसा ऐसे समय हुआ, जब दिवाली के लिए पटाखों की मांग बढ़ने लगती है। त्योहार के नजदीक आते ही पटाखों का निर्माण, पैकिंग और भंडारण तेज हो जाता है। लेकिन यदि इस दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी होती है, तो उत्सव की तैयारी कुछ ही पलों में जानलेवा हादसे में बदल सकती है।

लाइसेंस था या नहीं? जांच के घेरे में पटाखा कारोबार

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि रिहायशी इलाके में पटाखों का निर्माण किस तरह किया जा रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। शुरुआती जानकारियों में मकान के मालिक को पटाखा कारोबारी बताया गया है। हालांकि, संबंधित यूनिट के लाइसेंस की वैधता और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर जांच की बात सामने आई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि यूनिट के पास वैध लाइसेंस था या नहीं, अथवा लाइसेंस होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।



पटाखों का निर्माण और भंडारण सामान्य घरेलू गतिविधि नहीं है। इसमें आग लगने और विस्फोट का गंभीर जोखिम रहता है। ऐसे कारोबार के लिए लागू लाइसेंसिंग शर्तों, सुरक्षित परिसर, अनुमत मात्रा में भंडारण और अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाके में यदि इन मानकों की अनदेखी होती है, तो खतरा केवल कारोबार करने वाले परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है।

सीवान की घटना में स्थानीय स्तर पर निगरानी और संभावित लापरवाही की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के निर्देश पर जामो बाजार थाने के प्रभारी धीरज कुमार और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित किया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई। हालांकि, निलंबन को अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जांच के बाद ही जिम्मेदारी और लापरवाही की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।



पटाखों की बढ़ती मांग, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

दिवाली पर पटाखों की बिक्री कई कारोबारियों के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों में से एक होती है। मांग बढ़ने के साथ उत्पादन और भंडारण का दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में नियमों का पालन, सुरक्षित स्थान पर निर्माण और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है। कारोबार में तेजी या अधिक कमाई की उम्मीद किसी भी स्थिति में लोगों की सुरक्षा से समझौता करने का आधार नहीं बन सकती।

सीवान हादसा यह भी सवाल उठाता है कि पटाखों के निर्माण और भंडारण से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी कितनी प्रभावी है। क्या संबंधित विभाग समय-समय पर लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की जांच करते हैं? क्या रिहायशी इलाकों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती है? और यदि किसी परिसर में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? इन सवालों के जवाब केवल एक हादसे की जांच के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी हैं।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि हर पटाखा कारोबारी नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए जांच का उद्देश्य केवल पूरे कारोबार को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह पता लगाना होना चाहिए कि हादसे के पीछे असल वजह क्या थी, सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या रही।



दिवाली की असली रोशनी सुरक्षा में है

दिवाली अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर उम्मीद की जीत का प्रतीक है। लेकिन जब पटाखों के निर्माण या भंडारण में लापरवाही के कारण किसी परिवार को अपनों की जान गंवानी पड़े, तो त्योहार की खुशियों पर गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। सीवान की घटना बताती है कि पटाखों का इस्तेमाल ही नहीं, उनका निर्माण और भंडारण भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।

इस हादसे के बाद जरूरी है कि संबंधित विभाग पटाखा निर्माण और भंडारण करने वाली इकाइयों की जांच करें, लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित करें और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही, लोगों को भी संदिग्ध गतिविधियों या असुरक्षित भंडारण की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए।

दिवाली पर घरों को रोशन करना, अपनों के साथ खुशियां बांटना और उत्सव मनाना हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन त्योहार का असली आनंद तभी है, जब उसकी तैयारी में किसी की जिंदगी दांव पर न लगे। सीवान का हादसा एक चेतावनी है कि रोशनी के इस पर्व पर सुरक्षा को नजरअंदाज करने की कीमत बेहद भारी हो सकती है।





बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली की खपत का सटीक रिकॉर्ड रखना, रीडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना और उपभोक्ताओं को बिलिंग से जुड़ी समस्याओं से राहत देना है। लेकिन नोएडा के कुछ इलाकों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क स्मार्ट मीटरों की कनेक्टिविटी में बाधा बन रहा है। इसके चलते मीटर से बिजली खपत का डेटा सर्वर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) अब रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। निगम का लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों में मीटरों की कनेक्टिविटी सुधारना है, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर होने के कारण डेटा का नियमित आदान-प्रदान प्रभावित होता है।

साढ़े चार लाख बिजली उपभोक्ता, 40 हजार से ज्यादा परिसरों में स्मार्ट मीटर

नोएडा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 4.5 लाख बताई गई है। इनमें 40 हजार से अधिक परिसरों में सिम आधारित स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ये मीटर सामान्य परिस्थितियों में मोबाइल नेटवर्क के जरिए बिजली खपत का डेटा केंद्रीय सर्वर तक भेजते हैं। इससे बिजली विभाग को मीटर की रीडिंग और खपत की निगरानी करने में मदद मिलती है।

हालांकि, बेसमेंट, घनी आबादी वाले इलाकों और कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सिग्नल कमजोर होने से डेटा ट्रांसमिशन प्रभावित हो सकता है। जब मीटर की जानकारी समय पर सर्वर तक नहीं पहुंचती, तो रीडिंग और निगरानी की प्रक्रिया में परेशानी आती है। ऐसे में विभाग को वैकल्पिक संचार तकनीक की जरूरत महसूस हुई है।

क्या है RF तकनीक और कैसे करेगी काम?

RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक में डेटा भेजने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सिम आधारित मीटरों के विपरीत, इस व्यवस्था में मीटरों के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क या मेश नेटवर्क के जरिए डेटा आगे भेजा जा सकता है। इससे हर मीटर के लिए सीधे मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

विद्युत निगम के अनुसार, नोएडा में दो हजार से अधिक RF मीटर सक्रिय हो चुके हैं। अब कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से तकनीक में बदलाव किया जाएगा, ताकि मीटरों का डेटा केंद्रीय सर्वर तक पहुंच सके।

इस तकनीक का फायदा उन इलाकों में अधिक हो सकता है, जहां मोबाइल सिग्नल के कारण स्मार्ट मीटर की कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। हालांकि, इसकी सफलता स्थानीय नेटवर्क कवरेज, उपकरणों की क्षमता और तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

क्या गलत बिलिंग की शिकायतें भी होंगी दूर?

स्मार्ट मीटर की कनेक्टिविटी बेहतर होने से बिजली खपत के डेटा को समय पर प्राप्त करने और रीडिंग की निगरानी में मदद मिल सकती है। इससे मीटर रीडिंग से जुड़ी कुछ परेशानियां कम होने की उम्मीद है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कमजोर नेटवर्क और गलत बिलिंग दो अलग-अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। RF तकनीक मुख्य रूप से संचार और डेटा ट्रांसमिशन की बाधा दूर करने के लिए अपनाई जा रही है; इससे हर तरह की बिलिंग शिकायत अपने आप खत्म होने की गारंटी नहीं है।

यदि किसी उपभोक्ता को बिजली बिल में गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसे मीटर की रीडिंग, बिल में दर्ज खपत और पिछले बिलों का मिलान करना चाहिए। समस्या बनी रहने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

RF तकनीक का विस्तार होने पर बिजली विभाग को मीटरों से डेटा प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है। इससे रीडिंग की निगरानी, खपत का रिकॉर्ड रखने और मीटर रीडरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को भी उम्मीद है कि तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाली परेशानियों में कमी आएगी।

हालांकि, योजना का वास्तविक असर सर्वे पूरा होने, कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में उपयुक्त उपकरण लगाए जाने और सिस्टम के सुचारु संचालन के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल यह कदम नोएडा में स्मार्ट मीटर की कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में एक तकनीकी समाधान है। इसकी सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि क्या इससे डेटा समय पर सर्वर तक पहुंचता है और उपभोक्ताओं की वास्तविक शिकायतों में कमी आती है।







ऋषभ कांत छाबड़ा
विशेष संवाददाता

मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी पर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या के बाद शव के टुकड़े नीले ड्रम में रखे गए और सबूत छिपाने के लिए उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया। जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

रविता और अमरदीप को भी फांसी

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप की हत्या का मामला भी सुर्खियों में रहा। पुलिस के मुताबिक, अमित की पत्नी रविता का अमरदीप के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची और गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई। मामले की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2026 को अदालत ने रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद मेरठ में पति की हत्या से जुड़े दूसरे मामलों की भी चर्चा तेज हो गई।



अंजलि पर पति की हत्या की साजिश का आरोप

मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव में राहुल की हत्या का मामला भी चर्चा में है। राहुल खेती-बाड़ी और पशुपालन करता था। पुलिस का आरोप है कि उसकी पत्नी अंजलि का पड़ोसी अजय के साथ प्रेम संबंध था। 1 नवंबर 2025 की रात राहुल को गांव के बाहर मंदिर के पास बुलाया गया, जहां अजय ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी। पुलिस ने अंजलि और अजय की भूमिका की जांच की। इस मामले में अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है और सुनवाई जारी है।

कोमल पर छह लाख की सुपारी देने का आरोप

बीएसएफ जवान नैन सिंह की हत्या के मामले में भी उनकी पत्नी कोमल का नाम सामने आया। पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को मामले का खुलासा करते हुए कोमल, उसके मौसेरे भाई गुलशन समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, कोमल ने गुलशन के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि हत्या के लिए छह लाख रुपये की सुपारी दी गई और रकम जुटाने के लिए कोमल ने अपने गहने गिरवी रखे। इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई जारी है।

दामिनी पर बीमा की रकम के लिए हत्या का आरोप

मेरठ के भंडौरा गांव में स्कूल संचालक अतुल कुमार की हत्या का मामला भी गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में है। पुलिस के मुताबिक, अतुल की पत्नी दामिनी का स्कूल वैन चालक तुषार पायला के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि दोनों ने 20 लाख रुपये की बीमा रकम पाने और साथ रहने के इरादे से अतुल की हत्या की योजना बनाई। पुलिस की जांच में जहरीले सांप के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।

दो मामलों में सजा, तीन फैसलों का इंतजार

मेरठ के इन पांच मामलों में मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, अंजलि, कोमल और दामिनी से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई और सुनवाई जारी है। इन घटनाओं में प्रेम संबंधों के साथ हत्या की साजिश और आर्थिक लाभ जैसे पहलू सामने आए हैं। हालांकि, हर मामले की परिस्थितियां अलग हैं। जिन मामलों में फैसला नहीं आया है, उनमें आरोप अदालत में साबित होना बाकी है। अब इन तीन मामलों की सुनवाई पर नजरें टिकी हैं।







बबली अंसारी
विशेष संवाददाता

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट-1' रिलीज से पहले ही चर्चा में है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में तेजी देखने को मिल रही है। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। फिल्म का बजट, इसकी स्टारकास्ट, दमदार विजुअल इफेक्ट्स और भारतीय महाकाव्य की कहानी इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर रहे हैं। हालांकि, एडवांस बुकिंग के आंकड़े उत्साहजनक जरूर हैं, लेकिन फिल्म को रिलीज से पहले ही सुपरहिट घोषित करना जल्दबाजी होगी।

₹4,000 करोड़ का बजट, सितारों से सजी रामायण

'रामायण' को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के दोनों भागों का कुल बजट करीब ₹4,000 करोड़ हो सकता है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक दोनों फिल्मों के बजट का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है।

फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं, जबकि नमित मल्होत्रा इसके निर्माता हैं। रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। अरुण गोविल और लारा दत्ता भी फिल्म की स्टारकास्ट का हिस्सा हैं।

फिल्म की खासियत इसका भव्य सिनेमाई पैमाना है। इसे IMAX के लिए तैयार किया गया है और विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी DNEG जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनी संभाल रही है। संगीत के लिए ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने साथ काम किया है। भारतीय महाकाव्य को आधुनिक तकनीक और बड़े पर्दे के अनुभव के साथ पेश करने की कोशिश फिल्म को खास बनाती है।

एडवांस बुकिंग में तेजी, NCR बना बड़ा बाजार

'रामायण: पार्ट-1' की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर को शुरू हुई। ट्रेड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Sacnilk के मुताबिक, 23 अक्टूबर तक भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब ₹8.27 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े में सिनेमाघरों की ओर से ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। इन्हें हटाने पर बुकिंग का आंकड़ा करीब ₹6.25 करोड़ था। इस दौरान लगभग 1.47 लाख टिकटों की बिक्री दर्ज की गई। शहरों के हिसाब से दिल्ली-NCR फिल्म के प्रमुख बाजारों में शामिल रहा, जबकि मुंबई में भी अच्छी बुकिंग देखने को मिली। हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी टिकटों की बिक्री दर्ज की गई है। विदेशों में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई हैं।

इन आंकड़ों से फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करेगी। वास्तविक ओपनिंग कलेक्शन टिकटों की बिक्री, शो की संख्या, दर्शकों की प्रतिक्रिया और रिलीज के दिन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

पार्ट-2 की रिलीज पर सवाल, बंगाल में टैक्स-फ्री का ऐलान

'रामायण' को दो भागों में रिलीज करने की योजना है। पहले भाग के बाद दूसरा भाग दिवाली 2027 में लाने की तैयारी थी। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दूसरे भाग की शूटिंग और बड़े युद्ध दृश्यों पर अधिक समय देने के लिए इसकी रिलीज दिवाली 2028 तक टाली जा सकती है। फिलहाल निर्माताओं की ओर से नई रिलीज तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फिल्म को राज्य में टैक्स-फ्री किए जाने की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य में दर्शकों को टिकट की कीमतों के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता का एक बड़ा कारण रामायण की कहानी से जुड़ा भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। बड़े बजट, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी टीम और लोकप्रिय कलाकारों की मौजूदगी ने इसकी चर्चा को और बढ़ाया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 'रामायण: पार्ट-1' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? एडवांस बुकिंग का शुरुआती रुझान फिल्म के लिए सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन इसका असली इम्तिहान रिलीज के बाद होगा। कहानी, अभिनय, संगीत और विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों को कितना प्रभावित करते हैं, यही तय करेगा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं।





मेष

करियर और कारोबार: नई जिम्मेदारियां, मतभेद से बचें, साझेदारी में सोच-समझकर निर्णय लें।

धन और आर्थिक स्थिति: जल्दबाजी से बचें, खर्चों का हिसाब रखें, उधार देने में सावधानी।

प्रेम और परिवार: रिश्तों में समझ बढ़ाएं, नए रिश्तों की संभावना।

स्वास्थ्य: आराम और व्यायाम पर ध्यान दें।

मासिक सलाह: गुस्से में बड़ा फैसला न लें।

वृषभ

करियर और कारोबार: स्थिरता पर ध्यान, नई योजनाओं की तुलना करें, ग्राहकों से संबंध मजबूत करें।

धन और आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ सकता, बजट बनाएँ, निवेश से पहले जोखिम समझें।

प्रेम और परिवार: पारिवारिक चर्चा, जीवनसाथी का सहयोग, भावनाएं स्पष्ट करें।

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या, खानपान पर ध्यान।

मासिक सलाह: आर्थिक स्थिरता और भरोसे को प्राथमिकता दें।

मिथुन

करियर और कारोबार: संवाद व संपर्क से अवसर, दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।

धन और आर्थिक स्थिति: आय के नए विकल्प, एक साथ कई योजनाओं से बचें, बकाया रकम पर ध्यान दें।

प्रेम और परिवार: समय बिताएं, गलतफहमियां दूर करें, नए संपर्क संभव।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान, ब्रेक लें, नींद पूरी करें।

मासिक सलाह: योजनाएं व्यवस्थित रखें।

कर्क

करियर और कारोबार: जिम्मेदारियों में संतुलन, नई जिम्मेदारी से पहले जरूरत समझें, पारदर्शिता रखें।

धन और आर्थिक स्थिति: परिवार पर खर्च, बचत बढ़ाएँ, बड़े फैसले में सावधानी।

प्रेम और परिवार: नजदीकी बढ़ेगी, जीवनसाथी की भावनाएं समझें, पुरानी बात सुलझाएँ।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति, आराम और मनोरंजन।

मासिक सलाह: परिवार और करियर दोनों को समय दें।

सिंह

करियर और कारोबार: आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, नई चुनौतियाँ, विस्तार से पहले आकलन करें।

धन और आर्थिक स्थिति: संतुलन रखें, दिखावे से बचें, निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह।

प्रेम और परिवार: अपनी बात रखें, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा, परिवार में खुशी।

स्वास्थ्य: पर्याप्त आराम, व्यायाम और संतुलित खानपान।

मासिक सलाह: आत्मविश्वास बनाए रखें, फैसलों में दूसरों की राय लें।

कन्या

करियर और कारोबार: योजनाओं की समीक्षा, अधुरे काम पूरे करें, बारीकियों पर ध्यान दें।

धन और आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण, निजी जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च, बचत योजना बनाएँ।

प्रेम और परिवार: आलोचना से बचें, दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, परिवार के साथ समय।

स्वास्थ्य: नींद, संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि।

मासिक सलाह: सब कुछ परफेक्ट करने के दबाव में न रहें।

तुला

करियर और कारोबार: नए संपर्क, पुराने रिश्तें मजबूत, टीम के साथ काम लाभकारी।

धन और आर्थिक स्थिति: नए विकल्प, खर्च और बचत में संतुलन, बकाया भुगतान पर ध्यान।

प्रेम और परिवार: मधुरता बनाए रखें, साथ समय बिताएं, मतभेद बातचीत से सुलझाएं।

स्वास्थ्य: मानसिक सुकून, थकान को नजरअंदाज न करें।

मासिक सलाह: दूसरों को खुश करने के साथ अपनी जरूरतों का ध्यान रखें।

वृश्चिक

करियर और कारोबार: क्षमता साबित करने का अवसर, नई जिम्मेदारी, योजनाएं लागू करने से पहले व्यवहारिकता जांचें।

धन और आर्थिक स्थिति: निवेश, कर्ज, खर्चों की समीक्षा, जल्दबाजी में पैसा न लगाएँ।

प्रेम और परिवार: स्पष्टता रखें, संदेह से बचें, खुलकर बातचीत करें।

स्वास्थ्य: संतुलन बनाए रखें, तनाव कम करें।

मासिक सलाह: जरूरी मुद्दों पर व्यावहारिक कदम उठाएँ।

धनु

करियर और कारोबार: सीखने और नई योजनाओं पर काम, प्रशिक्षण से अनुभव, गुणवता पर ध्यान।

धन और आर्थिक स्थिति: आय-व्यय का आकलन, यात्रा/शिक्षा पर खर्च, बड़े फैसलों में सोचें।

प्रेम और परिवार: यात्रा/आयोजन की योजना, रिश्तों में सकारात्मकता, नए अवसर।

स्वास्थ्य: आराम के लिए समय, नियमित दिनचर्या।

मासिक सलाह: बड़े लक्ष्य तय करें, व्यावहारिक योजना बनाएं।

मकर

करियर और कारोबार: लंबित कार्य व्यवस्थित, मेहनत और अनुशासन, पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करें।

धन और आर्थिक स्थिति: कर्ज, निवेश, बचत पर व्यावहारिक दृष्टिकोण, अनावश्यक खर्च कम करें।

प्रेम और परिवार: परिवार को समय दें, भविष्य की योजनाओं पर बातचीत।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम।

मासिक सलाह: ऊर्जा और समय का सही प्रबंधन करें।

कुंभ

करियर और कारोबार: साझेदारी, नेटवर्किंग, नए विचारों पर काम, समझौते की शर्तें समझें।

धन और आर्थिक स्थिति: संतुलन बनाए रखें, बड़ी रकम से पहले जानकारी जुटाएँ, बचत करें।

प्रेम और परिवार: खुलकर बातचीत, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, अपनी भावनाओं का महत्व दें।

स्वास्थ्य: आराम के लिए समय, अनियमित दिनचर्या से बचें।

मासिक सलाह: नए लोगों से जुड़ना फायदेमंद, भरोसा करने से पहले समझें।

मीन

करियर और कारोबार: कामकाज व्यवस्थित, जिम्मेदारियां बढ़ें, भुगतान और संचालन पर ध्यान।

धन और आर्थिक स्थिति: अनुशासन बनाए रखें, अचानक खर्च के लिए बचत रखें, कर्ज से पहले क्षमता का आकलन करें।

प्रेम और परिवार: भावनाओं को स्पष्ट करें, रिश्तों में संवेदनशीलता, परिवार के साथ समय।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक आराम।

मासिक सलाह: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, फैसलों में व्यावहारिक पक्ष भी देखें।

शुभ रंग

लाल, पीला, हरा, नीला

इन रंगों का उपयोग आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा।

नवंबर 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां

- 02 नवंबर – गोवर्धन पूजा
- 06 नवंबर – देवोत्थान एकादशी
- 08 नवंबर – सूर्य का तुला राशि में प्रवेश
- 11 नवंबर – प्रदोष व्रत
- 19 नवंबर – संकष्टी चतुर्थी
- 20 नवंबर – गुरु का मार्गी होना
- 24 नवंबर – धनतेरस
- 25 नवंबर – नरक चतुर्दशी
- 26 नवंबर – दीपावली
- 27 नवंबर – गोवर्धन पूजा / भाई दूज

नवंबर 2026 का कैलेंडर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

NOW NOIDA UPDATE

MAGAZINE

Noida की हर खबर, अब आपके साथ

NOW NOIDA UPDATE मैगज़ीन



अपने बिज़नेस को दें
Noida में पहचान!

- LOCAL NEWS UPDATES
- BUSINESS PROMOTION
- EVENTS & LIFESTYLE
- REAL ESTATE & OPPORTUNITIES

ADVERTISEMENT SIZE		RATE (रुपये में)
Full Page	(8.5" x 11")	₹ 70,000
Half Page	(8.5" x 5.5")	₹ 40,000
Quarter Page	(4.25" x 5.5")	₹ 24,000
Front Inside Cover		₹ 1,00,000
Back Cover		₹ 1,20,000
Double Spread	(17" x 11")	₹ 1,40,000

BOOK YOUR AD TODAY!

SPECIAL OFFER!
EXTRA DISCOUNT ON MULTIPLE INSERTION BOOKINGS!

9891114598
7428827715

Email: info@nownoida.com
mukesh.mishra@nowuttarpradesh.com

www.nownoida.com

ZELTON POWER

POWERING A BETTER TOMORROW

SMARTER POWER. STRONGER TOMORROW.

Advanced Lithium Power Solutions for **Homes, Businesses & Industries.**



LOWER COST
Lower running & maintenance cost

LONGER LIFE
More cycles, more savings

SILENT OPERATION
No noise. Just reliable power.

CLEAN & SUSTAINABLE
No emissions during use

MINIMAL MAINTENANCE
Hassle-free performance for years

INTELLIGENT POWER SOLUTIONS FOR EVERY NEED



HOME POWER
Reliable backup for your home and loved ones.

OFFICE BACKUP
Uninterrupted power for productivity that never stops.

INDUSTRIAL POWER
Engineered for heavy loads and critical operations.

SOLAR SOLUTIONS
Store clean energy for a sustainable tomorrow.

RELIABLE. EFFICIENT. SUSTAINABLE.
BUILT FOR TODAY. READY FOR TOMORROW.

ZELTON POWER

Delivering advanced lithium power solutions with innovation, quality and trust – to power progress for a better tomorrow.

zeltronpower.com
+91 74288 27714
care@zeltronpower.com